



संक्षिप्त

समाचार

पूर्व केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला

कार के शीशे तोड़े

गुरदासपुर (एजेंसी)। पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के काफिले पर हमला हो गया। बिट्टू शुक्रवार को अमृतसर से पटानकोट में यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बिट्टू ने कहा कि बटाला (गुरदासपुर) के पास काफिले को घेरा गया। इसके बाद हमला कर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। उन पर टमाटर और अंडे फेंके गए। पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पीते रवनीत बिट्टू को वाय+ सिक्कोरिटी



मिली हुई है। माहौल बिगड़ते देख उनके सुरक्षाकर्मी तुरंत उन्हें एक घर में ले गए। बिट्टू ने आरोप लगाया कि फतेहगढ़ बुड़िया से एएपी के हलका इंचार्ज जोबन रंधावा के समर्थकों ने लंगर की आड़ में उन पर हमला किया है। उन्होंने 2 आरोपियों को भी पकड़ा। इस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी डरी हुई है। घबरा गई है। इसलिए रवनीत बिट्टू पर हमला हुआ। सोचिए एक वाय+ सिक्कोरिटी वाले और पूर्व मंत्री के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा, ये पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर भी दिखाता है। पंजाब की सभी 117 सीटों को कवर करने वाली भाजपा की 4 हजार किमी लंबी नशामुक्त यात्रा शुक्रवार से पटानकोट से शुरू हो गई है। जिसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने रवाना किया।

राहुल उवाच, वोट चोरी के बाद अब पार्टी की चोरी

- राहुल बोले-यह सिर्फ ममता बनर्जी की लड़ाई नहीं बची है

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न और नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के आदेश की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है। वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद अब पार्टी चोरी हो रही है।



राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा- पहले शिवसेना, फिर एनसीपी और अब तृणमूल कांग्रेस। हर बार एक ही पैटर्न- बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं। फिर उसका चुनाव

चिन्ह छीन लिया जाता है। उन्होंने लिखा- जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं। वोट चोरी। सरकार चोरी। अब पार्टी चोरी - ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं। 21 जून 2022 को शिवसेना में उदय ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट अलग हुए थे। इसी तरह 2 जुलाई 2023 को एनसीपी में शरद पवार और अजित पवार गुट अलग हुए थे। कांग्रेस नेता की वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी ने असंवैधानिक रूप से टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न पर कब्जा कर लिया है। यह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से मोदी जी को दर रात दिया गया जन्मदिन का तोहफा है।

मनुभाकर और तेजिंदर तूर होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक

एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी आज, जापान में हो रहे हैं गेम्स

नई दिल्ली (एजेंसी)। स्टार निशानेबाज मनु भाकर और शॉपुट में गत चैंपियन तेजिंदर पाल सिंह तूर को एशियन गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में



भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियन गेम्स में इवेंट्स की शुरुआत हो गई है लेकिन अभी ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई है। ओपनिंग सेरेमनी के बाद मेडल इवेंट होंगे। 20वें एशियाई खेल जापान के आइची प्रान्त और

सदियों बाद फिर जाग उठा हरिपुर, यमुना तट पर गूंजा आस्था का जयघोष

21 फीट ऊंची मां यमुना की प्रतिमा का अनावरण, हरिघाट का लोकार्पण और यमुना-कृष्ण मंदिर का शिलान्यास

2016 में लोक पंचायत ने देखा था पुर्नजागरण का सपना, अब 'यमुना कृष्ण धाम' के रूप में बदलने लगी तस्वीर

जयन्त प्रतिनिधि। देहरादून : जौनसार-बावर की ऐतिहासिक धरती पर गुरखार का दिन लंबे समय तक याद रखा जाएगा। यमुना तट पर बसे ऐतिहासिक हरिपुर में आस्था, इतिहास और विकास का संगम दिखाई दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां यमुना की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, हरिघाट का लोकार्पण तथा मां यमुना-कृष्ण मंदिर का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत-महात्मा, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी पहुंचे।

मां यमुना के जयघोष से हरिपुर का वातावरण भक्तिमय हो उठा। वर्षों से अपने प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित होते देखने की प्रतीक्षा कर रहे क्षेत्रवासियों के लिए यह आयोजन केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हरिपुर के पुर्नजागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में सामने आया। हरिपुर के पुर्ननिर्माण की कहानी करीब एक दशक पुराने संकल्प से जुड़ी है। लोक पंचायत ने वर्ष 2016 में हरिपुर के प्राचीन स्वस्व और धार्मिक महत्व को पुर्नजीवित करने की परिकल्पना की थी। लोक पंचायत ने हरिपुर में हरिद्वार की तर्ज पर घाट निर्माण, मां यमुना की भव्य प्रतिमा, यमुना-कृष्ण मंदिर, यमुना आरती, धार्मिक मेले तथा आसपास के प्राचीन धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और विकास का विचार रखा। संगठन के अनुसार उस समय यह केवल एक संकल्प था, लेकिन लगातार सामाजिक प्रयासों के बाद आज हरिपुर में उस परिकल्पना के कई महत्वपूर्ण हिस्से धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। यमुना तट पर विकसित हरिघाट के लोकार्पण के साथ हरिपुर को धार्मिक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाएं बढ़ी हैं। लोक पंचायत की परिकल्पना है कि यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालु हरिपुर पहुंचें, मां यमुना के दर्शन और यमुना स्नान के बाद अपनी यात्रा आगे बढ़ाएं। इसके लिए हरिपुर को सुविधायुक्त तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता होगी।

21 फीट की मां यमुना प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र
यमुना-कृष्ण धाम परिसर में स्थापित 21 फीट ऊंची मां यमुना की प्रतिमा अब हरिपुर की धार्मिक पहचान का प्रमुख केंद्र बन गई है। प्रतिमा के अनावरण के साथ ही श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। लोक पंचायत के अनुसार प्रतिमा स्थापना के पीछे वर्षों से किए जा रहे सामाजिक प्रयास और जनसहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

हरिपुर: इतिहास के पन्नों में दर्ज एक प्राचीन केंद्र



हरिपुर को स्थानीय ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। लोक पंचायत के अनुसार प्राचीन काल में इस क्षेत्र को 'हरि क्षेत्र' के नाम से जाना जाता था। यमुना के साथ अमलावा, नौर और टैंस नदियों से जुड़े संगम क्षेत्र के कारण भी हरिपुर का धार्मिक महत्व बताया जाता है। प्राचीन व्यापारिक मार्गों और जलमार्गों से जुड़े संदर्भ हरिपुर की ऐतिहासिक भूमिका को और महत्वपूर्ण बनाते हैं। समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं और अन्य परिस्थितियों ने इस क्षेत्र के स्वस्व को बदल दिया और कभी महत्वपूर्ण रहा हरिपुर धीरे-धीरे अपने पुराने वैभव से दूर होता गया।

हरिपुर के आसपास इतिहास का खजाना
हरिपुर को विकसित करने की सबसे बड़ी विशेषताओं में इसके आसपास मौजूद धार्मिक और पुरातात्विक स्थल भी हैं। जगतग्राम में अश्वमेध यज्ञ से जुड़े पुरातात्विक अवशेष, कालसी का अशोक शिलालेख, कल्प त्रिभि मंदिर, व्यास क्षेत्र और गंगवेवा जैसे स्थल इस पूरे क्षेत्र की विरासत को महत्वपूर्ण बनाते हैं। यदि इन स्थलों को हरिपुर के साथ जोड़कर एक समग्र धार्मिक एवं पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाता है तो क्षेत्र में तीर्थयात्रा और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिल सकता है।

हरिपुर से यमुनोत्री तक धार्मिक पर्यटन

कौरिखोर की परिकल्पना

लोक पंचायत की परिकल्पना हरिपुर को केवल स्थानीय तीर्थ स्थल तक सीमित रखने की नहीं है। संगठन चाहता है कि इसे यमुनोत्री यात्रा के प्रमुख पड़ाव के रूप में विकसित किया जाए। इसके साथ हरिपुर से कालसी, चक्राता, हनोल, लाखामंडल और जौनसार-बावर के अन्य धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़कर एक व्यापक पर्यटन सर्किट विकसित किए जाने की संभावना है।

धर्म के साथ रोजगार की नई राह

हरिपुर के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय रोजगार भी है। धार्मिक पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर होमस्टे, होटल, स्थानीय भोजन, परिवहन, गाइड सेवा, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद, पूजा सामग्री और छोटे व्यापार जैसी गतिविधियों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे जौनसार-बावर के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार और स्वरोजगार के विकल्प मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

लोक पंचायत: सामाजिक सरोकारों से हरिपुर तक

लोक पंचायत का गठन वर्ष 2016 में सामाजिक सरोकारों को केंद्र में रखकर किया गया। संगठन का कहना है कि उसका उद्देश्य जौनसार-बावर की सामाजिक एकता, लोक संस्कृति, बोली, पारंपरिक वेशभूषा और ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण करना है।

जज एनटीए दफतर जाएंगे, एजेंसी ने कहा था-एग्जाम सिस्टम फुलप्रूफ बनाया



नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जरूरत पड़ने पर नीट परीक्षा सिस्टम की जांच के लिए जज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिस का दौरा करेंगे। वे देखेंगे कि परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराने के इंतजाम वास्तव में काम कर रहे हैं या नहीं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अलोक अराधे की बेंच यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट, पैमा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इसमें एनटीए को भंग करने और पेपर लीक

रोकने के लिए मजबूत निगरानी सिस्टम की मांग की गई है। इससे पहले सरकार ने 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नीट परीक्षा सिस्टम फुलप्रूफ है। इसमें संध लगाना मुश्किल है। कोर्ट ने एनटीए को अपने सुधारों और अब तक हुई प्रगति का ब्योरा वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया है। इससे परीक्षा व्यवस्था में हो रहे बदलावों की जानकारी सार्वजनिक होगी। एनटीए के लिए पर्याप्त स्थायी कर्मचारी और विशेषज्ञ स्टाफ रखने की जरूरत पर चर्चा हुई।

रणवीर सिंह ने लिया 1000 बेटियों की पढ़ाई का संकल्प

- लालबागचा राजा पहुंचे थे, बोले-आशा है, इससे बप्पा प्रसन्न होंगे



मुंबई (एजेंसी)। एक्टर रणवीर सिंह ने मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा पंडाल में पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत 1000 बेटियों की शिक्षा में मदद करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि बप्पा का आशीर्वाद लेकर आगे के सफर के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। एक इंटरव्यू में रणवीर ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है यहां आकर। जो पिछला साल गुजरा है, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए खुशियों से भरा रहा, बप्पा की कृपा से। तो यहां आए हैं उनके दर्शन करने, उनको धन्यवाद कहने और उनका आशीर्वाद लेने, आगे के सफर के लिए, जीवन के सफर के लिए।

जी-20 देशों में सबसे आगे होंगे 'हिंदुस्तानी'

- इस साल सबसे तेज बढ़ सकती है 'भारतीय' अर्थव्यवस्था ● मूडीज ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6 से 7 फीसदी किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की अर्थव्यवस्था इस साल 120 देशों में सबसे तेज बढ़ सकती है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने यह अनुमान लगाया है। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है। मूडीज का कहना है कि मिडिल ईस्ट में तनाव और संघर्ष के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर अनुमान से काफी कम पड़ा है। मजबूत घरेलू खपत, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में सुधार के संकेत लगातार मजबूत बने हुए हैं।

कच्चे तेल की कीमतें और महंगाई अभी भी चिंता का विषय

मूडीज ने चेतावनी दी है कि भले ही जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया गया है, लेकिन जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार बजट घाटा कम करने के अपने लक्ष्य पर कायम है। सरकार इसे पिछले साल के 4.4 फीसदी से घाटकर वित्त वर्ष 2026-27 में 4.3 फीसदी करना चाहती है। हालांकि ऊर्जा क्षेत्र में राहत देने के लिए ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ सकती है।



डिजिटल परीक्षा चरणबद्ध तरीके से होगी

कोर्ट ने कहा कि लिखित परीक्षा से डिजिटल परीक्षा की ओर बदलाव अचानक नहीं किया जा सकता। इसे धीरे-धीरे लागू करना होगा, ताकि नई व्यवस्था में परेशानी न हो। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा सुधारों को लेकर वकील और राज्य अपने सुझाव तय हैं-मेल के जरिए भेज सकते हैं। इन सुझावों को सुधार प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली हाईड-पावर्ड पैनल की पहली अंतरिम रिपोर्ट सितंबर के अंत तक आने की संभावना है।

घरेलू मांग और सर्विस सेक्टर बने ग्रोथ के मुख्य पिलर

मूडीज के मुताबिक, भारत की इस तेज ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह देश में बढ़ती मांग है। लोगों का खर्च बढ़ा है और कंपनियों को निवेश में भी तेजी बनी हुई है। कंपनियों और प्राइवेट सेक्टर की ओर से नए निवेश के संकेत मिलने लगे हैं। वहीं, सर्विस सेक्टर भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से उबरने में मदद मिली है। मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग बीएएच 3 पर बरकरार रखी है। साथ ही, देश का आउटलुक 'स्टेबल' यानी स्थिर रखा है।

जम्मू-कश्मीर में लश्कर मददगारों के ठिकानों पर छापेमारी

चीन में बनी 2 ग्रेनेड, एक पिस्तौल-गोलियां बरामद, 4 दिन पहले 3 आतंकी मददगार गिरफ्तार हुए थे



और मोहम्मद मुस्ताक के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी आतंकीयों को पनाह देने के साथ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते थे।

एफआईआर नंबर की जांच के दौरान मॉड्यूल का पता चला- पुलिस के मुताबिक, राजौरी के धरमसाल थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 95/2026 की जांच के दौरान

इस मॉड्यूल का पता चला। जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। उन्होंने आतंकीयों को रहने की जगह दी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद की। आरोपियों ने 2023 में रियासी के चसाना में मुठभेड़ में मारे गए आतंकीयों की भी मदद की थी। जांच में यह भी पता चला कि उन्होंने कई आतंकी समूहों को रहने की जगह और दूसरी जरूरी मदद दी। आरोपियों ने आतंकीयों की मदद की थी।

पाकिस्तान में बैठे 2 आतंकीयों की संपत्ति अटैच

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा में पाकिस्तान में रह रहे 2 आतंकीयों से जुड़ी संपत्तियां अटैच की हैं। पुलिस के मुताबिक, कुपवाड़ा के कचामा में 15 कनाल 7 मरला जमीन और 2 मकान अटैच किए गए हैं। ये संपत्तियां अब्दुल मजीद कुरेशी और परवेज अहमद कुरेशी के नाम पर दर्ज हैं। दोनों कचामा के रहने वाले हैं और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान में रहकर आतंकी गतिविधियां चला रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नयिन प्रभात ने इन संपत्तियों को अटैच करने की मंजूरी दी है। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में 16 सितंबर की रात सुरक्षाबलों ने दो आतंकीयों को मार गिराया था। सुरक्षाबलों ने सर्व ऑपरेशन शुरू कर यह कार्रवाई की थी। जिले के मजाला इलाके में आतंकीयों के छिपे होने की सूचना मिली थी।

दूरदर्शी नीतियां बन रही आधार विकास की ओर अग्रसर उत्तराखंड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड की हाल में शुरू की गई पहलें समग्र विकास के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। यह जहां एक ओर राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान दे रही है, वहीं उत्तराखंड को प्रगति और परिवर्तन की राह पर तेजी से आगे बढ़ा रही हैं।



राज्य के स्थानीय लोगों से बात करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी



नियुक्ति पत्र वितरित करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी



“ 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड, इन दोनों ही स्तंभों को लगातार मजबूत कर रहा है। ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ”

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

“ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। तीर्थाटन एवं पर्यटन की दृष्टि से लोग यहां आयें, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं ताकि पर्यटक शीतकाल में पर्यटन के साथ तीर्थों का भी आनन्द ले सकें। ”

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

सुशासन से सामाजिक समानता और व्यापक कल्याण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए उत्तराखंड में सुधारों की निर्मल धारा प्रवाहित कर रहे हैं। राज्य सरकार उत्तराखंड को समानता, पारदर्शिता और अनंत अवसरों की भूमि बनाने की दिशा में सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है।

समान नागरिक संहिता: व्यक्तिगत कानूनों का एकीकरण

7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की। इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव-इन संबंधों से जुड़े कानूनों को एक ढांचे में जोड़ा गया। सिर्फ चार महीनों में मई 2025 तक 1.5 लाख से अधिक पंजीकरण हुए। ऐप, पोर्टल और गांव में बनाए गए केंद्रों की मदद से 98% गांवों से आवेदन पहुंचे। यह कानून महिलाओं को बराबरी और न्याय देता है, जबकि इसमें अनुसूचित जनजातियों की परंपराओं को संरक्षण के लिए छूट दी गई है।



एटी-चीटिंग कानून: निष्पक्ष परीक्षाओं की गारंटी

प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए

उत्तराखंड ने सख्त एटी-चीटिंग कानून लागू किया है। पेपर लीक, नकल या भर्ती घोटाले अब संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध हैं। सजा में 10 साल तक की कैद, भारी जुर्माना और अवैध संपत्ति की जफती शामिल है। इस कदम ने युवाओं का भरोसा बहाल किया है और मेरिट आधारित भर्ती प्रणाली को मजबूती मिली है।

महिलाओं को 30% आरक्षण: सशक्तिकरण की दिशा में कदम

उत्तराखंड लोक सेवा अधिनियम, 2022 (जनवरी 2023 से लागू) के तहत राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया गया है। यह सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी सभी वर्गों की महिलाओं पर लागू होता है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में यह निर्णय महिलाओं को अवसर और समृद्धि प्रदान कर रहा है।

ये सुधार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साझा दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जिसमें प्रगतिशील, सशक्त और सक्षम उत्तराखंड के निर्माण की झलक दिखती है, जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है, सुशासन को आधार बनाते हुए अपनी परंपराओं का भी सम्मान करता है। समान नागरिक संहिता (UCC) सुधार समाजिक कुरीतियों को समाप्त कर नागरिकों के व्यापक कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। निरंतर प्रयासों से राज्य में न्यायपूर्ण और संतुलित वातावरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जनसांख्यिकी की रक्षा: जबरदस्ती धर्मांतरण पर रोक

उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम (2018, संशोधित 2022 व 2024) जबरदस्ती, धोखे से या

प्रलोभन देकर धर्मांतरण को दंडनीय अपराध बनाता है। इसमें विशेष रूप से नाबालिगों, महिलाओं और एससी/एसटी समुदायों से जुड़े मामलों में 10 साल तक की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान है। यह

कानून कमजोर वर्गों की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द को सुनिश्चित करता है।

भूमि कानून 2025: पर्यावरण और धरोहर की सुरक्षा

फरवरी 2025 में विधानसभा ने नया भूमि सुधार कानून पारित किया। इसके तहत बाहरी लोगों को अधिकांश जिलों (हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर) में कृषि व बागवानी भूमि खरीदने पर रोक है। खरीदारों को शपथ पत्र देना होगा और तय नियमों का पालन करना होगा। इस कानून का उद्देश्य भूमि माफियाओं पर रोक, पर्यावरण की रक्षा और जमीन स्थानीय समुदायों के पास सुरक्षित रखना है।

ये सभी सुधार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की साझा दृष्टि को दर्शाते हैं, जिसमें प्रगतिशील, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की छवि झलकती है, जो सामाजिक न्याय, सुशासन और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करता है।

श्रीअन्न से समृद्धि की ओर कृषि में आई नई क्रांति

‘मंडुआ’ की कीमतें बढ़ाने से लेकर विदेशी फलों की खेती को बढ़ावा देने तक राज्य की नीतियां किसानों को सशक्त बना रही हैं और ग्रामीण समृद्धि को सुनिश्चित कर रही हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पारंपरिक खेती को मजबूत करने और बागवानी क्रांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य सरकार ने बाजरा, सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है, जिससे पोषण सुरक्षा और किसानों की आय, दोनों में वृद्धि हो रही है।

2022 से मंडुआ (फिगर मिलेट) को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जा रहा है और इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम और आंगनवाड़ी पोषण योजनाओं में शामिल किया गया है। 2023 में लॉन्च हुई स्टेट मिलेट मिशन के तहत उत्पादन, भंडारण और

जागरूकता अभियानों में तेजी आई है। इसके परिणामस्वरूप सिर्फ दो साल में मंडुआ का समर्थन मूल्य 68% बढ़ गया है।

उत्तराखंड कीवी नीति (2025–31) और ड्रैगन फ्रूट योजना (2025–28) के तहत किसानों को कीवी के लिए 70% और ड्रैगन फ्रूट के लिए 80% सब्सिडी दी जा रही है। ये पहलें किसानों को उच्च-मूल्य वाले फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इसके जरिए किसान अपनी आय बढ़ाते हैं और टिकाऊ, आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाते हैं।

इन कदमों से उत्तराखंड में समृद्ध, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए मजबूत कृषि ढांचा तैयार हो रहा है।



आईटी और डिजिटल तकनीक आधारित सेवाओं की शुरुआत



मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित कई सेवाओं की शुरुआत की है। इनमें डिजिटल उत्तराखंड ऐप, सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य (S3Waas) प्लेटफॉर्म पर निर्मित 66 वेबसाइटें, शहरी क्षेत्रों में कचरा संग्रहण वाहनों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग के लिए जीआईएस आधारित वेब एप्लिकेशन, बेहतर नागरिक सेवा के लिए 1905 सीएम हेल्पलाइन में इन्ोवेशन, अतिक्रमण निगरानी के लिए वेब आधारित एप्लिकेशन शामिल हैं। कुछ प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं:

- उत्तराखंड में भविष्य की चुनौतियों को पूरा करने के लिए नेक्स्ट-जेनरेशन डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें समर्पित डिजास्टर रिकवरी तंत्र होगा।
- राज्य में ‘एआई मिशन’ जल्द शुरू किया जाएगा, जिसे ‘सेंटर ऑफ एक्सिलेंस’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
- सुशासन को आगे बढ़ाते हुए राज्य में नेक्स्ट-जेनरेशन रिमोट सेंसिंग और ड्रोन एप्लिकेशन सेंटर विकसित किया जाएगा।
- सरकार राज्य में समर्पित आईटी केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम करेगी।

एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का नया रोडमैप तैयार

नीतिगत सुधारों, वित्तीय प्रोत्साहनों और संस्थागत सहयोग के साथ उत्तराखंड सरकार इनके लिए मजबूत इकोलॉजी तैयार कर रही है।



उत्तराखंड सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य को स्टार्टअप्स, हरित उद्योगों और उच्च-गुणवत्ता वाले स्थानीय उत्पादों का वैश्विक हब बनाना है। नई एमएसएमई नीति टिकाऊ, समावेशी और रोजगार सृजित करने वाले उद्यमों पर जोर देती है। साथ ही, निवेशकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुनिश्चित करती है।

राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये न केवल रोजगार के अवसर सृजित करते हैं, बल्कि मूल्यवर्धित उत्पाद भी बनाते हैं। सरकार के नए फोकस के तहत स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही, नवीकरणीय और हरित ऊर्जा आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और प्रदूषण-मुक्त टिकाऊ उद्योगों का विकास किया जा रहा है। इन प्रयासों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, राज्य की जीडीपी को मजबूती मिलेगी, निवेश आकर्षित होगा और समावेशी विकास को बल मिलेगा।

नीतिगत प्रोत्साहन और कार्ययोजना

राज्य की नीति नए और मौजूदा दोनों उद्यमों को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। मौजूदा औद्योगिक इकाइयों में तकनीकी को बेहतर बनाकर प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही, पूंजी और बाजार तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। निवेश आकर्षित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन लागू किए जा रहे हैं।

सरकार वन डिस्ट्रिक्ट, टू प्रोडक्ट (ओडीटीपी) योजना और जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग को भी बढ़ावा दे रही है, ताकि उत्तराखंड के विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पहचान मिले। इसके अलावा, राज्य की नीतियां राष्ट्रीय कार्यक्रमों

जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना से जोड़ी जा रही हैं, ताकि मेक इन उत्तराखंड ब्रांड को व्यापक पहचान मिल सके।

समावेशी और टिकाऊ विकास

सरकार का लक्ष्य है कि एमएसएमई सेक्टर का विकास समावेशी तरीके से हो। इसके लिए महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय व विशेष क्षमताओं वाले उद्यमियों को सहायता दी जा रही है। इन समूहों को अपने कारोबार बढ़ाने और नए अवसरों तक पहुंच दिलाने के लिए निवेशकों और कारोबारियों के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन का काम करेंगे। महिलाओं और दिव्यांग उद्यमियों के लिए विशेष हेल्पलाइन सेवाएं भी शुरू की जा रही हैं।

संस्थागत सहयोग की मजबूती

जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ताकि उद्यमियों को तकनीकी सुविधाएं, प्रोजेक्ट तैयारी और परामर्श सेवाएं मिल सकें। सिंगल विंडो विलयन सिस्टम को और सरल बनाया जा रहा है, ताकि उद्योगों को तेजी से अनुमोदन मिल सके। साथ ही, निदेशालय स्तर पर एक निवेश के प्रोत्साहन और सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो निवेशकों और कारोबारियों के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन का काम करेंगे। महिलाओं और दिव्यांग उद्यमियों के लिए विशेष हेल्पलाइन सेवाएं भी शुरू की जा रही हैं।

विपणन और वैश्विक पहुंच

उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देने के लिए सक्रिय है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पोटेंट्स का उपयोग बढ़ाया जा रहा है, ताकि स्थानीय उद्यमों को वैश्विक पहचान मिले। इस पहल का उद्देश्य है कि नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय परंपराओं को संरक्षित रखा जाए और उत्तराखंड को टिकाऊ व समावेशी उद्योगों का हब बनाया जाए।

वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी

नई एमएसएमई नीति के अंतर्गत उद्यमों को ये वित्तीय लाभ प्रदान किए जा रहे हैं:

- श्रेणी के आधार पर 100% तक स्टार्टअप इयूटी की वापसी
- संयंत्र और मशीनरी पर 50% तक की पूंजी सब्सिडी
- प्राथमिक श्रेणियों के लिए 10 लाख रुपये तक की अतिरिक्त पूंजी निवेश सब्सिडी
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग उद्यमियों को 5% अतिरिक्त सब्सिडी
- श्रेणी के अनुसार 21 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी वापसी
- 500 किलोवाट तक के स्वीकृत लोड वाले नए उद्यमों के लिए पांच वर्षों तक बिजली शुल्क की वापसी
- जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेडईई) सर्टिफिकेशन के तहत मान्यता
- स्वर्ण, रजत और कांस्य श्रेणियों में प्रमाणित इकाइयों को 75,000 रुपये प्रति इकाई मौद्रिक पुरस्कार

पर्यटन और रोजगार को बल

उत्तराखंड में सड़कों का कार्यालय पर्यटन क्षेत्र के लिए अहम साबित हुआ है। होमस्टे, रिवर वैली कैम्पिंग, एडवेंचर ऑपरेटर्स और चारधाम यात्रा सेवाओं जैसे व्यवस्थापक लंबे समय तक संचालित हो पा रहे हैं और उन्हें कम लॉजिस्टिक जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। इनका सीधा फायदा उत्तराखंड के नागरिकों को मिल रहा है।

उत्तराखंड में ई-वे की वजह से वीकेंड विजिटर्स भी बढ़ी हैं, जिससे ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे शहरों को अतिरिक्त आय हो रही है। बेहतर सड़क नेटवर्क ने कम-जाने पहचाने स्थलों को भी पर्यटन मानचित्र पर ला दिया है, जिससे इको-टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को प्रोत्साहन मिल रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। कुल मिलाकर उत्तराखंड का समग्र विकास हो रहा है, जिसमें नागरिकों का हित संपूर्ण है।

धामी सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को मिला विस्तार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वस्थ भारत के विजन के अनुरूप उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सभी के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित निवेश और सुधार किए जा रहे हैं। पिछले चार वर्षों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है।

2021 में अल्मोड़ा और 2024 में हरिद्वार में दो नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जा चुके हैं। इस विस्तार से 200 नई एमबीबीएस सीटें जुड़ी हैं, जिससे राज्य में कुल सीटों की संख्या बढ़कर 625 हो गई है। इसके अतिरिक्त, पिथौरागढ़ और रुद्रपुर में नए कॉलेज स्थापित



करने की तैयारी है, जहां संबद्ध अस्पताल पहले से ही कार्यरत हैं। किच्छ में एम्स (सेटेलाइट सेंटर) पर

भी काम प्रगति पर है, जबकि एम्स ऋषिकेश ने राज्य की पहली एयर खुलेंस सेवा शुरू की है। इसके अलावा, हरद्वाला (देहरादून) में 300 बेड का कैसर अस्पताल भी तैयार कर लिया गया है।

अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एक अहम कार्यक्रम के रूप में उभरी है, जिसके तहत करीब 60 लाख लाभार्थियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक का केशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना देशभर के 30,000 से अधिक अस्पतालों में मान्य है।

जिला और तहसील स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का लक्ष्य न केवल स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है, बल्कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए नए रोजगार और करियर के सुनहरे अवसर भी सृजित करना है।

भूस्खलन की जद में ऐतिहासिक चूना धारा, अस्तित्व पर मंडरा रहा संकट



दुगड्डा में भूस्खलन की जद में आया ऐतिहासिक प्राकृतिक जलस्रोत चूना धारा।

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : ऐतिहासिक नगरी दुगड्डा की बात हो और चूना धारा का जिक्र न हो, तो कहानी कुछ अधूरी सी लगती है। कभी

अहम भूमिका रही है। ब्रिटिश दौर से लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन तक यह प्राकृतिक जलस्रोत लोगों की प्यास बुझाता रहा। ऐतिहासिक धरोहर भूस्खलन की चपेट में आकर अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है।

20वीं शताब्दी के चौथे दशक तक दुगड्डा संयुक्त गढ़वाल जनपद का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गढ़वाल के सीमांत गांव नीति-माणा तक खाद्यान्न की आपूर्ति दुगड्डा से होती थी। क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा के विरोध और डोला-पालकी आंदोलन की अलख भी इसी नगरी से जली। गढ़वाल कमिश्नरी के

1945 में दुगड्डा पहुंचे थे। सिलगाड और लंगूगाड नदियों के मध्य बसे दुगड्डा में स्थित चूना धारा पिछले करीब सवा सौ वर्षों से लोगों की प्यास बुझा रही है। स्थानीय मान्यता के अनुसार, वर्षों पहले पहाड़ी पर हुए भूस्खलन के बाद यह प्राकृतिक जलस्रोत अस्तित्व में आया था। ब्रिटिश शासनकाल में भी अधिकारी इस जलस्रोत का पानी पीते थे, वहीं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोग भी यहां अपनी प्यास बुझाते थे।

अब खुद संकट में है जलस्रोत

वर्तमान में चूना धारा की पहाड़ी पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ी से मलबे के साथ बड़े-बड़े बोलखर भी गिर रहे हैं। भूस्खलन के कारण दुगड्डा नगर पालिका की ओर से चूना धारा के आसपास कराया गया सौंदर्यीकरण कार्य पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि भूस्खलन का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो प्राकृतिक जलस्रोत के अस्तित्व पर भी संकट गहरा सकता है। चूना धारा का संबंध केवल दुगड्डा की प्राकृतिक विरासत से नहीं, बल्कि नगर की पेयजल व्यवस्था से भी रहा है। वर्ष 1945 में दुगड्डा को नोटिफाइड एरिया

घोषित किया गया था। इसके बाद वर्ष 1946 में चूना धारा से दुगड्डा नगर के लिए पेयजल लाइन बिछाई गई। इस लाइन के जरिए नगर में सार्वजनिक नलों तक पानी पहुंचाया जाता था। बाद में वन विभाग की ओर से ग्राम ऐता के लिए भी इसी जलस्रोत से लीज पर पेयजल लाइन बिछाई गई।

आंदोलनकारियों की भी बुझाई प्यास

चूना धारा ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन तक के कई दौर देखे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान दिल्ली कूच के लिए निकले कई आंदोलनकारियों ने यहां अपने वाहन रोके और जलस्रोत का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। ऐसे में चूना धारा महज एक प्राकृतिक जलस्रोत नहीं, बल्कि दुगड्डा के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की भी जीवंत निशानी है।

अब जरूरत इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की भूस्खलन प्रभावित पहाड़ी का जल्द भू-वैज्ञानिक परीक्षण करवाकर सुरक्षा के ठोस उपाय करने चाहिए, ताकि चूना धारा को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके।

ग्रामीणों ने की सड़क और बिजली की मांग

कर्णप्रयाग। कपौरी क्षेत्र के ग्रामीणों ने सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कर्णप्रयाग-नैनीसैंण मोटर मार्ग की मरम्मत व चौड़ीकरण करने, खत्याड़ी से बगोली आमसोड तक शीघ्र डामरीकरण, धार डूंगरी-मेखुरा मार्ग खोलने, डोंटाला में भूधंसाव के लिए सुरक्षा दीवार और कई अन्य मार्गों के निर्माण की मांग उठाई। प्रशासन ने ज्ञापन को उच्च अधिकारियों को भेजने का आश्वासन दिया। इस दौरान उत्तम तोपाल, खिल देव सिंह, रमेश बिष्ट और संजय कण्डवाल सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

संक्षिप्त समाचार

खेल महाकुंभ का आगाज, मैदान में दिखा खिलाड़ियों का दमखम



जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : विकासखंड पौड़ी में खेल महाकुंभ-2026 का शुक्रवार को रांसी स्टेडियम में विधिवत शुभारंभ हुआ। पांच दिवसीय आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे युवा खिलाड़ियों ने उत्साह और जोश के साथ विभिन्न खेल स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया। शुभारंभ अवसर पर पौड़ी विधायक प्रतिनिधि ओमप्रकाश जुगुनान ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल महाकुंभ ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाने और उन्हें आगे बढ़ने का बेहतर मंच उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने और लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करने का आह्वान किया। प्रतियोगिताओं के दौरान रांसी स्टेडियम में खिलाड़ियों के बीच मुकाबलों की लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और दमखम का प्रदर्शन किया। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिताएं 22 सितंबर तक चलेंगी और इसी दिन समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। शुभारंभ दिवस पर 800 मीटर अमिट भंडारी पौड़ी ब्लॉक प्रथम, द्वितीय स्थान लकी रुडोला कल्जीखाल और तृतीय स्थान अभिनाश नेगी कोट विकासखंड ने प्राप्त किया। विजेता खिलाड़ियों को मुख्यातिथि के हाथों मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख पौड़ी अस्मिता नेगी, ब्लॉक प्रमुख कल्जीखाल गीता देवी, जिला पंचायत सदस्य अनुज कुमार, कनिष्ठ प्रमुख कोट नीरज पटवाल, क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी नरेश रावत, युवा कल्याण अधिकारी कोट मनोज कुमार, बीडीओ दृष्टि आनंद, विधायक पौड़ी पीआरओ सुभाष रावत आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण नेगी ने किया।

बदरीनाथ से आ रही टीजीएमओयू की बसों को रोका, उतारे यात्री

कर्णप्रयाग। जीएमओयूलि, रूपकुंड पर्यटन विकास समिति की बसों को ऋषिकेश में रोके जाने का विरोध किया गया। विरोध के तहत जीएमओयूलि और रूपकुंड से जुड़े कर्मचारियों और वाहन संचालकों ने दूसरे दिन भी बदरीनाथ से आ रही टीजीएमओयू की बसों को आगे नहीं जाने दिया। कर्मचारियों और वाहन चालकों ने वाहनों को वहीं रोककर उसमें बैठी सवारियों को अन्य वाहनों की मदद से उनके गंतव्यों के लिए रवाना किया। कर्मचारियों और वाहन चालकों ने कहा कि जब तब जीएमओयूलि, रूपकुंड की बसों का देहरादून से नियमित संचालन नहीं होता तब तक विरोध जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन भी किया। शुक्रवार सुबह 9:30 बजे जीएमओयूलि और रूपकुंड से जुड़े कर्मचारियों और वाहन संचालकों ने बदरीनाथ से सवारी ले कर आ रही टीजीएमओयू की बस को उमा देवी तिरहे पर रोक दिया। इसके बाद वाहन पुलिस चौकी के पास पार्किंग में खड़ा किया गया और उसमें बैठी सवारियों को अन्य वाहनों से अपने गंतव्यों तक पहुंचाया। पूर्वाह्न 11 बजे बदरीनाथ से एक और बस आई उन्होंने उसे भी रोक दिया और सवारियों को दूसरे वाहनों से भेजा गया।

पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने का दिया संदेश

जयहरीखाल महाविद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : भक्तदर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयहरीखाल, पौड़ी गढ़वाल में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को स्वच्छता शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता, जिम्मेदारी एवं सहभागिता की भावना विकसित करना रहा। शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वच्छता के महत्व



भक्तदर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयहरीखाल में शपथ लेते हुए प्राध्यापक एवं छात्र-छात्राएं।

पर्यावरण संरक्षण तथा अपने आसपास स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम में नमामि गंगे के नोडल

अधिकारी डॉ. अजय रावत ने नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए स्वच्छ एवं निर्मल जल स्रोतों के संरक्षण के महत्व को बताया। उन्होंने

छात्र-छात्राओं ने विद्यालय परिसर की सफाई कर जैविक व अजैविक कूड़ेदान में एकत्र किया कचरा

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : स्वच्छ भारत मिशन के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक चलाए जा रहे 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत पब्लिक इंटर कॉलेज सुरखेत में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अभियान की थीम 'स्वच्छता में सहभाग: स्वच्छ भारत, विकसित भारत' रखी गई है। अभियान का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं एनएसएस के गढ़वाल मंडल कार्यक्रम समन्वयक पुष्कर सिंह नेगी ने छात्र-छात्राओं को स्वच्छता की शपथ दिलाकर किया। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों में

स्वच्छता की आदत विकसित करना, स्वच्छता को जनांदोलन का रूप देना तथा स्वच्छता के प्रति व्यापक जनभागीदारी और नागरिक स्वाभिव्यक्ति को बढ़ावा देना है। अभियान के दूसरे दिन विद्यालय के युथ एवं ईको क्लब, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा यूसकर्व विज्ञान चेतना केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में छात्र-छात्राओं ने विद्यालय परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान वृक्ष वाटिका, उद्यान वाटिका, कक्षा-कक्षों, प्रयोगशाला, कार्यालय, पुस्तकालय, एमडीएम कक्ष एवं किचन तथा शौचालयों की साफ-सफाई की गई। विद्यार्थियों ने सफाई के दौरान

दीप जलाकर दिया पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश

लैसडौन छावनी में 17 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता पखवाड़ा

जयन्त प्रतिनिधि। लैसडौन : स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत छावनी परिषद कार्यालय लैसडौन के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों और परिषद कर्मियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। छावनी परिषद के सेनेटरी अधिकारी दीपक मिश्रा ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक पूरे छावनी क्षेत्र में मनाया जाएगा। इस दौरान सफाई अभियान, जागरूकता रैली, विद्यालयों में प्रतियोगिताएं और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाए



जाएंगे। इस अवसर पर स्वच्छता ही सेवा का बैनर लेकर उपस्थित लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों की जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। छावनी परिषद की सीढ़ियों पर दीप जलाकर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने



पब्लिक इंटर कॉलेज सुरखेत में स्वच्छता अभियान चलाते हुए छात्र।

एकत्रित कचरे को अलग-अलग करते हुए जैविक और अजैविक कूड़ेदानों में जमा किया। इस दौरान विद्यार्थियों को

कचरे के उचित निस्तारण और स्वच्छता बनाए रखने के प्रति भी जागरूक किया गया।

प्रधान संघ ने ब्लॉक कार्यालय में की नारेबाजी

देवाला। प्रधान संघ ने दस सूत्री मांगों के लिए ब्लॉक कार्यालय में नारेबाजी की। संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर 28 सितंबर को तालाबंदी की चेतावनी दी। साथ ही सभी 29 विभागों को पंचायतों को हस्तांतरित करने की मांग की। प्रधान संघ के अध्यक्ष खिलाल सिंह बिष्ट और महामंत्री नरेंद्र बिष्ट के नेतृत्व में प्रधानों ने प्रदर्शन किया। संघ ने ग्राम प्रधानों को न्यूनतम 20 हजार रुपये मानदेय देने, जिला योजना की बैठक बनाने, मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी 600 रुपये और कुशल मजदूरों की 800 रुपये करने आदि की मांग की।

का संदेश दिया गया। सेनेटरी अधिकारी ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वच्छ मोहल्ला, स्वच्छ लैसडौन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी नागरिकों को आगे आना होगा।

राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की कार्यकारिणी का हुआ विस्तार

जयन्त प्रतिनिधि कोटद्वार : राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, जिला कोटद्वार की संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी एवं मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। कार्यकारिणी में ब्लॉक अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, सचिव, सोशल मीडिया प्रभारी एवं सह प्रभारी की नियुक्ति की गई है। जिला संयोजक रुपेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि संदेश नेगी को जयरीखाल ब्लॉक अध्यक्ष, अजीत पाल सिंह को नैनीडांडा ब्लॉक अध्यक्ष, दिनेश चौहान को खिण्णीखाल ब्लॉक अध्यक्ष, सोहन सिंह रावत को यमकेश्वर ब्लॉक अध्यक्ष, राजेन्द्र सिंह नेगी को दुगड़डा ब्लॉक अध्यक्ष, राकेश को डारीखाल ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जिला कार्यकारिणी में सुमन वावर, मेहरबान सिंह, बबन सिंह, ओमचन्द्र, मो0 तसलीम अहमद को उपाध्यक्ष, चन्द्रमोहन सिंह नेगी, विपिन सिंह रावत, मो0 शादीम, मोहनदास को महासचिव, पीताम्बर रावत, सीमा देवी, योगेश कुमार, हसीना बेगम, दीपचन्द्र को सचिव, दीपक रावत को सोशल मीडिया प्रभारी, दिनेश चन्द्र को सोशल मीडिया सह प्रभारी, कमलेश कान्त कुकरेती और उपेन्द्र नेगी को प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिला संयोजक ने नव नियुक्त पदाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे संगठन की नीतियों एवं सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने, जनहित के मुद्दों को उठाने तथा संगठन को ग्राम पंचायत स्तर तक मजबूत एवं सक्रिय बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

उत्तर रेलवे	
ई-नीलामी सूचना	
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/पी.एस., (ए.सी.ओ) उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के द्वारा मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर एम.पी.एस., ऑटोमेटिक वैंडिंग मशीन (A/VM) कार्य को IREPS के माध्यम से ठेके पर देने हेतु ई-बोलियों दिनांक 09.10.2026 को तथा वाटर वैंडिंग मशीन (WVM) कार्य को IREPS के माध्यम से ठेके पर देने हेतु ई-बोलियों दिनांक 12.10.2026 को www.ireps.gov.in पर आमंत्रित की जाती है, जिसकी विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तें www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।	3253/2026
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ	

उत्तर रेलवे	
निविदा सूचना	
टेन्डर नं. Sr. DEN-IV/Publication/26-27	दिनांक 17.09.2026
भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अतिरिक्त/चतुर्थ द्वारा निम्नलिखित ई टेंडर संख्या जिनके बन्ध होने की तिथि व समय प्रत्येक सामने अंकित हैं। जो उसी दिन 16.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। निम्नलिखित टेंडर संख्या के अन्तर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की कीमत तथा धरोहर राशि का मुरादाबाद निविदावला द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आनलाइन मुरादाबाद करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट बैंक चेक डिपॉजिट स्वीड आदि स्वीकार्य नहीं होगा। टेंडर से संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।	
टेंडर संख्या	196-DRM-MB-26-27 Date - 17.09.2026
कार्य का नाम	Construction of Type - II quarters at Najibabad
टेंडर क्लोसिंग दिनांक	13.10.2026
टेंडर क्लोसिंग समय	16.00
अनुमानित लागत	5,34,50,292.62
धरोहर राशि	10,69,000.00
कार्य पूर्ण करने की अवधि	10 माह
निविदा आरंभ तिथि	29.09.2026
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ	
3237/26	

उत्तर रेलवे				
निविदा सूचना				
क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (₹0)	बिड सिक्यूरिटी	कार्य के पूर्ण करने की समय अवधि
1.	31 / वरिष्ठ मं.वि.अभि./सा./मुरा./2026 /- ADEN/ CH के अधीन ZRTA परिसर में 4 स्मार्ट क्लबास रूम के प्रावधान एवं गेट संख्या 3 के सौंदर्यकरण संबंधी विद्युत कार्य एवं मोतीचूर, ऋषिकेश, डोईवाला में उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म (PF 1 एवं 2) के साथ FOB रैप, च्यालापुर में मौजूदा FOB के लिए रैप के विद्युत कार्य।	7140314.90 (जीएसटी सहित)	142800.00	6 (छः) माह
2.	32 / वरिष्ठ मं.वि.अभि./सा./मुरा./2026 /-एबीएसएस के लिए विद्युत कार्य: मुरादाबाद डिवीजन के आंगला स्टेशन का उन्मथन।	11393392.14 (जीएसटी सहित)	227900.00	12 (बारह) माह
3.	33 / वरिष्ठ मं.वि.अभि./सा./ मुरा./2026 /- मुरादाबाद मंडल के Sr.DEN-1 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर पंप स्थापना एवं संबंधित सहायक उपकरणों के प्रावधान संबंधी विद्युत कार्य।	2874151.98 (जीएसटी सहित)	57500.00	4 (चार) माह
कार्यालय का पता जहाँ से निविदा प्रपत्र जारी किया गया है		विद्युत शाखा, मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय मुरादाबाद	वेबसाइट एवम् कार्यालय का पता	वेबसाइट www.ireps.gov.in मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय मुरादाबाद।
निविदा प्रपत्र जमा करने तथा खुलने की दिनांक व समय		निविदाएं दिनांक 09.10.2026 को 15.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं जो उसी दिन 15:00 बजे खोली जायेंगी।		
निविदा सूचना सं: 30/2026		दिनांक: 17.09.2026		
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ				
3236/26				

मुख्यमंत्री ने मियांवाला में 8.64 करोड़ की लागत से विकसित ‘जल सृष्टि पार्क’ का किया लोकार्पण

जयन्त प्रतिनिधि। देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत मियांवाला, देहरादून में लगभग 8 करोड़ 64 लाख की लागत से विकसित ‘जल सृष्टि पार्क’ का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को नए पार्क की सौगात मिलने पर बधाई दी और इसे स्वच्छ, स्वस्थ एवं हरित देहरादून के संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि रायपुर क्षेत्र के लोगों के बीच इस सुंदर पार्क का लोकार्पण उनके लिए प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि ‘जल सृष्टि पार्क’ आधुनिक सुविधाओं और प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। पार्क को इस प्रकार विकसित किया गया है कि यहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं तक सभी आयु वर्ग के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पार्क के निर्माण के दौरान यहां पहले से मौजूद पुराने तालाब को समाप्त करने के बजाय उसका पुनर्जीवन किया गया है। उन्होंने कहा कि तालाब के संरक्षण और उसके आसपास सुविधाओं के विकास से इस

स्थान को नई पहचान मिली है। तालाब के मध्य सुंदर आइलैंड विकसित किया गया है तथा लोगों के मनोरंजन के लिए पेडल बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि अब रायपुर क्षेत्र के लोगों को देहरादून में ही एक खूबसूरत प्राकृतिक स्थल के साथ ‘नैनीताल जैसी फीलिंग’ का अनुभव प्राप्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में जल और जंगल को केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं माना गया, बल्कि इन्हें जीवन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा समझा गया है। ऐसे में पुराने तालाबों और जल स्रोतों का पुनर्जीवन केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारी विरासत को बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल एवं प्रकृति को सुरक्षित रखने का भी महत्वपूर्ण प्रयास है। कार्यक्रम में विधायक उमेश शर्मा काऊ, मेयर सौरभ थपलियाल, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवाड़ी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

सौगंड डैम से मजबूत होगी देहरादून की पेयजल व्यवस्था

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून लगातार विस्तार ले रहा है और बढ़ती



आबादी के साथ पानी की आवश्यकता भी बढ़ रही है।

ऐसे में सौगंड डैम जैसी महत्वपूर्ण परियोजना पर भी कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे भविष्य में देहरादून की पेयजल व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान बाढ़ और जलभराव की समस्या से लोगों को राहत दिलाने के लिए रायपुर

क्षेत्र में नदियों और बरसाती नालों पर बाढ़ सुरक्षा तथा चैनलाइजेशन के कार्य भी किए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि जहां सड़क की आवश्यकता हो वहां सड़क बने, जहां भयंजल की समस्या हो वहां पानी पहुंचे, जहां जलभराव हो वहां उसका स्थायी समाधान हो और जहां हरियाली की आवश्यकता हो वहां सुंदर पार्क विकसित किए जाएं।

स्वाइन फ्लू एक मरीज प्रति घंटा से अधिक हुई संक्रमण की रफ्तार

देहरादून। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू (इंग्लिश: एच1एन1) के मामलों में लगातार दर्ज की जा रही बढ़ोतरी चिंता पैदा करने लगी है। 24 घंटे में 24 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सितंबर महीने में स्वाइन फ्लू के मामलों में एकाएक बढ़ोतरी देखी गई है। एक सितंबर से अब मरीजों का प्रतिदिन के हिसाब से औसत 32 दर्ज किया गया है। यानी हर घंटे कम से कम एक मरीज संक्रमण की चपेट में आ रहा है। प्रदेश में अगस्त से अब तक 557 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इससे संक्रमित पांच लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने पांच में से दो लोगों के मौत का कारण सिर्फ स्वाइन फ्लू को बताया था। सितंबर महीने में एकाएक स्वाइन फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिस तरह से पूरे अगस्त महीने में सिर्फ 105 मरीज ही सामने आए थे वहीं सितंबर में 17 दिनों में ही 452 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हो गई।

विकास का उद्देश्य लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास किसी एक परियोजना का नाम नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाना है। जल सृष्टि पार्क भी इसी व्यापक सोच का हिस्सा है, जहां पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों के लिए मनोरंजन, स्वास्थ्य और प्रकृति से जुड़ने की सुविधाएं विकसित की गई हैं। उन्होंने इस कार्य के लिए एमडीडीए के अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में यह पार्क केवल रायपुर क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे देहरादून के लोगों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा।

पार्क को अपना समझकर स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने की अपील

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्रवासियों से अपील की कि सरकार पार्क का निर्माण कर सकती है, उसे सुंदर बना सकती है और सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, लेकिन उसे लंबे समय तक स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना सभी की साझा

जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से पार्क को केवल सरकारी संपत्ति न मानकर अपना पार्क समझने और अपने घर की तरह इसकी स्वच्छता एवं देखभाल करने का आग्रह किया। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों और युवाओं से पार्क का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बच्चे और युवा यहां खेलें, दौड़ें, योग करें और प्रकृति के बीच समय बिताएं, लेकिन इसके साथ पार्क और जलाशय की देखभाल की जिम्मेदारी भी समझें। सरकार और समाज के सामूहिक प्रयास से ही कोई विकास कार्य लंबे समय तक सुंदर और उपयोगी बना रह सकता है।एमडीडीए द्वारा मियांवाला, देहरादून में 8.64 करोड़ की लागत से विकसित यह जल सृष्टि पार्क एक बहुआयामी हरित एवं मनोरंजन स्थल है, जिसमें पुराने तालाब का पुनर्जीवन करते हुए उसके आसपास आधुनिक सुविधाओं का विकास किया गया है। पार्क में सुबह-शाम भ्रमण एवं दौड़ने के लिए जॉगिंग ट्रैक, योग के लिए योगा डेक, बालों के लिए चिकित्‍न पार्क, फूलों एवं वनस्पतियों की जानकारी देने वाला एजुकेशनल प्लावर गार्डन, आकर्षक लैंडस्केपिंग, हरित क्षेत्र तथा बैठने की सुविधाएं विकसित की गई हैं।

विकासनगर एनएच—507 पर फिर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

विकासनगर। राष्ट्रीय राजमार्ग—507 पर अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत गुरुवार को विभागीय टीम ने एक बार फिर अभियान चलाया। दुकानदारों को पूर्व में दी गई 10 दिन की मोहलत समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग की निर्धारित सीमा में किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई तेज की गई। अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारियों के साथ नगरपालिका कर्मचारियों और पुलिस बल की मौजूदगी रही। टीम ने बाजार क्षेत्र में सड़क एवं निर्धारित सीमा में लगाए गए साइन बोर्ड, टिनशेड और अन्य अस्थायी निर्माण को हटया। कई स्थानों पर दुकानों के आगे रखे बोर्ड एवं अन्य सामान को टीम ने अपने कब्जे में लिया।

विभागीय टीम के बाजार क्षेत्र में पहुंचते ही अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों में हलचल मच गई। टीम ने मौके पर दुकानदारों को सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए तथा कार्रवाई के दौरान सामने आए सामान को हटया। फुटपाथ पर खड़े वाहनों को लेकर उठे सवाल अतिक्रमण हटाओ अभियान के बीच कार्रवाई के

दायरे को लेकर सवाल भी सामने आए। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा रही कि कई स्थानों पर फुटपाथ और सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण पैदल राहगीरों की परेशानी होती है। ऐसे में लोगों का सवाल है कि यदि अभियान का उद्देश्य सड़क एवं पैदल आवाजाही को सुचारु करना है, तो फुटपाथ अथवा सड़क किनारे खड़े वाहनों के खिलाफ भी समान रूप से कार्रवाई कब होगी।

10 दिन की मोहलत के बाद दोबारा कार्रवाई बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग—507 पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पिछले कई दिनों से जारी है। अभियान के शुरुआती चरण में दुकानदारों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था। निर्धारित समय समाप्त होने के बाद विभाग ने दोबारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की है।

अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई को लेकर अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अभियान आगे किन क्षेत्रों तक पहुंचता है और सड़क, फुटपाथ तथा राष्ट्रीय राजमार्ग की निर्धारित सीमा को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए विभाग द्वारा आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।

सीसीटीएनएस में उत्तराखंड की राष्ट्रीय रैंकिंग सुधरी

देहरादून। ऋद्ध एंड त्रिनिमल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स परियोजना के तहत राज्य शीर्ष समिति की बैठक मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सीसीटीएनएस और आईसीजेएस 2.0 की प्रगति के साथ तकनीकी आधारभूत ढांचे, नेटवर्क कनेक्टिविटी, डेटा रिकवरी सेंटर, उपकरणों की उपलब्धता और सिस्टम इंटीग्रेटर से जुड़े विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जुलाई 2026 तक सीसीटीएनएस प्रगति डैशबोर्ड में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर 9वीं रैंक हासिल की है।

पिछली समीक्षा में राज्य 13वें स्थान पर था। इस तरह उत्तराखंड की रैंकिंग में चार स्थान का सुधार हुआ है। वहीं आईसीजेएस 2.0 डैशबोर्ड में उत्तराखंड देश में तीसरे स्थान पर है। इसके तहत ई—साक्ष्य, न्यायश्रुति, ई—समन, ई—साइन और मेडलीग सहित विभिन्न डिजिटल अनुप्रयोगों का क्रिमान्वयन किया जा रहा है। इन व्यवस्थाओं के जरिए पुलिस, अभियोजन, कारागार और न्यायिक प्रक्रिया के बीच डिजिटल समन्वय एवं कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

एनसीएलआई डैशबोर्ड में भी छह स्थान का सुधार

बैठक में एनसीएलआई डैशबोर्ड की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों के अनुसार 17 सितंबर 2026 तक उत्तराखंड 18वीं रैंक पर पहुंच गया है, जबकि पिछली समीक्षा में राज्य 24वें स्थान पर था। इस प्रकार राज्य की रैंकिंग में छह स्थान का सुधार दर्ज किया गया।

एक नजर

परशुराम महासभा ने बांटी रुद्राक्ष के पौधे

ऋषिकेश। परशुराम महासभा की ओर से रुद्राक्ष की पौध का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और सरोज डिमरी ने लोगों को रुद्राक्ष के पौधे वितरित किए। परशुराम सभा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के साथ धार्मिक आस्था को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। सभा के अध्यक्ष संदीप शास्त्री ने कहा कि रुद्राक्ष का पौधा लगाने से लोगों में धार्मिक प्रवृत्ति के साथ प्रकृति के प्रति जुड़ाव भी बढ़ेगा। परशुराम महासभा प्रत्येक वर्ष हरेला पर्व के अवसर पर रुद्राक्ष के पौधों का वितरण करती है। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में रुद्राक्ष के पौधों का वितरण किया जाए तो यह और भी शुभ माना जाता है। इस अवसर पर ओम प्रकाश शर्मा, प्यारे लाल जुगारन, राजेश कंडवाल, रीना शर्मा, अनिता रैना, केके शर्मा, अरुण शर्मा, बृजमोहन मनुड़ी, डीके मुद्गल, कुंवर सिंह रावत, देवेंद्र जोशी, विजय त्तुड़ी, प्रीति सग्ना, वीर सिंह, ज्ञान किशोर भट्ट, उनीयाल, विष्णु अग्रवाल, शैली उनीयाल, आलोक द्विवेदी, प्रेम दत्त बिजल्वान्ग, महानंद जुगारन, शिवम कंडवाल आदि मौजूद रहे।

दुकानों पर बंद हो सकती है डिजिटल पेमेंट सुविधा

ऋषिकेश। यूपीआई लेन-देन से जुड़े नए नियमों पर तीर्थनगरी के व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा दिया और अब दो हजार रुपये से अधिक के डिजिटल भुगतान पर टैक्स लगाने से छोटे-बड़े कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नियम वापस नहीं लिए गए तो दुकानों से यूपीआई बारकोड हटाकर डिजिटल भुगतान बंद किया जा सकता है। व्यापारियों के मुताबिक इससे ग्राहकों की नकदी पर निर्भर होना पड़ेगा और त्योहारी सीजन में एटीएम-बैंकों पर भीड़ बढ़ने के साथ कारोबार प्रभावित हो सकता है।

हल्द्वानी में निकाली कदली—कलश यात्रा

हल्द्वानी। आवाग विकास स्थित विवेकानंद विद्यालय में चल रहे मां नंदा-सुनंदा दिव्य ज्योति महोत्सव—2026 के तहत बृहस्पतिवार को कदली और कलश यात्रा निकाली गई। हिमतपुर बेजनाथ स्थित कालिका मंदिर पहुंची में कदली पूजन किया गया। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं पारंपरिक कुमाऊंजी परिधान व आभूषणों में शामिल हुईं। इस दौरान मां नंदा-सुनंदा के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। यात्रा में निशित शर्मा, हनुम सिंह कुंवर, प्रशांत नेगी, लाखन निगिल्टिया, पंडित मदन मोहन जोशी, सतेंद्र प्रसाद आदि शामिल हुए।

तल्ली हल्द्वानी, हल्दूचौड़ और बिंदुखता में बनेंगे नए बिजलीघर
हल्द्वानी। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने भविष्य में बिजली भार की संभावना को देखते हुए नए बिजलीघर बनाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पास, बिंदुखता और हल्दूचौड़ में बिजलीघर बनाने के लिए डीपीआर तैयार करने के साथ ही जमीन की तलाश में शुरू हो गई है। इन बिजलीघरों के बनने के बाद 50 हजार की आबादी को फायदा मिलेगा। शहर में पिछले एक दशक के मुकाबले बिजली की मांग में इजाफा हुआ है।

चम्पावत को हराकर देहरादून बना चैंपियन

देहरादून, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखंड के तत्वावधान में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालयी बालक वर्ग हॉकी प्रतियोगिता में जनपद देहरादून ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर—14 बालक वर्ग की विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर ली। 17 से 19 सितंबर 2026 तक आयोजित हो रही प्रतियोगिता के दूसरे दिन अंडर—14 वर्ग के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले गए। रोमांचक फाइनल मुकाबले में देहरादून ने चम्पावत को पराजित कर चैंपियन का खिताब हासिल किया। देहरादून की टीम की ओर से कप्तान अनुराग सिंह ने सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। वहीं, तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में नैनीताल ने अल्मोड़ा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।

सेमीफाइनल में भी दिखाया दम

फाइनल से पहले खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में देहरादून ने नैनीताल को 2—1 से पराजित किया। दूसरे सेमीफाइनल में चम्पावत ने अल्मोड़ा को 4—0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। विजेता और उपविजेता टीमों को अंतरराष्ट्रीय कबड्डी रेफरी एवं उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के टेक्निकल हेड मनोज नेगी ने ट्रॉफी एवं पदक प्रदान कर सम्मानित किया। अंडर—17 और अंडर—19 के मुकाबले भी जारी प्रतियोगिता के आगामी मुकाबलों में अंडर—19 वर्ग के पहले सेमीफाइनल में देहरादून और उष्मन सिंह नगर, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में पिथौरागढ़ और

ज्योलीकोट के बाद चोपड़ा में भी जलजनित बीमारी का खतरा

नैनीताल। ज्योलीकोट में जलजनित बीमारी के बढ़ते मामलों के बीच अब समीपवर्ती चोपड़ा गांव से भी चिंताजनक खबर सामने आई है। ग्रामीणों के अनुसार, चोपड़ा में बीते कुछ दिनों में 20 से 30 लोग बीमार हो चुके हैं जबकि 10 से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। कई लोगों में पीलिया के लक्षण सामने आने की बात कही जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर ग्रामीणों की जांच शुरू कर दी है।

चोपड़ा ज्योलीकोट का समीपवर्ती गांव है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों क्षेत्रों के बीच लोगों की लगातार आवाजाही रहती है। चोपड़ा के लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ज्योलीकोट बाजार पहुंचते हैं जबकि

कई बच्चे पढ़ने के लिए ज्योलीकोट के स्कूलों में जाते हैं। ऐसे में ज्योलीकोट में जलजनित बीमारी के प्रकोप के बाद चोपड़ा में भी लोगों के बीमार पड़ने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीण चंदन सिंह जीना ने बताया कि गांव के 10 से अधिक लोग उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती हैं।

ज्योलीकोट स्कूल और बाजार में पानी पीने से संक्रमण की आशंका
ग्राम प्रधान बीना जीना ने बताया कि चोपड़ा के ग्रामीणों का ज्योलीकोट में आना-जाना लगातार बना रहता है। उन्होंने आशंका जताई कि वहां पानी पीने या दूषित पानी के संपर्क में आने से लोगों की तबीयत खराब हो सकती है।

118 किमी दौड़कर कनासर पहुंचा विकासनगर एथलेटिक्स क्लब



विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। साथ ही बच्चों और युवाओं को नियमित रूप से खेल गतिविधियों से जुड़ने का संदेश दिया। क्लब के अनुसार अभियान का उद्देश्य केवल 185 किलोमीटर की दूरी पूरी

करना नहीं, बल्कि रास्ते में पड़ने वाले क्षेत्रों और विद्यालयों तक हूछेल से जुड़ो, नशे से दूर रहोह का संदेश पहुंचाना है। क्लब का मानना है कि खेल युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के साथ नशे जैसी

सामाजिक बुराइयों से दूर रखने का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं।

विकासनगर में हुआ रिले रन का स्वागत विकासनगर पहुंचने पर स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और व्यापार मंडल विकासनगर की ओर से रिले रन का स्वागत किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को खेलों के प्रति प्रेरित किया गया तथा नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि विकासनगर एथलेटिक्स क्लब लगातार खेल गतिविधियों और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित कर रहा है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों से जुड़ने का आह्वान किया।

हर पड़ाव तक पहुंचे नशामुक्ति का संदेश क्लब अध्यक्ष प्रभजोत सिंह ने कहा कि रिले रन का लक्ष्य सिर्फ 185 किलोमीटर की दूरी तय करना नहीं है।

जयन्त

संस्थापक : नरेन्द्र

उनियाल

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक नागेंद्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस बदरीनाथ मार्ग, कोटद्वार गढ़वाल (उत्तराखण्ड) से मुद्रित तथा बदरीनाथ मार्ग, कोटद्वार गढ़वाल (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित।

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र कोटद्वार, (गढ़वाल) उत्तरखण्ड होगा।

CONT. 9412081969

PRGI NO. 35469/79

संपादकीय

टैक्स पर बहस

ऑनलाइन भुगतान को लेकर लगने वाले टैक्स पर पूरे देश में विवाद लगभग गहराता ही जा रहा है और सरकारी नुमाइंदों को लाख समर्थित बयानों के बावजूद पूरे व्यापार जगत में हड़कंप मचा हुआ है। भ्रांतियां कहे या फिर सच इसे लेकर ग्राहक और व्यापारी दोनों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। या तो स्पष्ट है कि 2000 से ऊमर के भुगतान में भले ही सरकार व्यापारी से टैक्स वसूलने की बात कर रही है लेकिन टैक्स की यह मार निश्चित तौर पर उपभोक्ता के कर ही पड़ने वाली है। देशभर के व्यापार मंडल अब केंद्र सरकार से शुल्क व्यवस्था की पूर्ण समीक्षा करने की मांग कर रहे हैं। यह तो तय है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बाद अब व्यापारियों पर शुल्क का बोझ डालने से छोटे दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और आम कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है। सरकार के द्वारा ही पहले व्यापारियों को डिजिटल भुगतान की सुविधा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। अब यदि 2,000 से ऊमर के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है तो इसका असर छोटे व्यापारियों की लागत और लाभ पर नजर आएगा। छोटे कारोबार में पहले से ही विभिन्न खर्चों का दबाव है। ऐसे में प्रत्येक डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क नई आर्थिक चुनौती खड़ी कर सकता है। फिलहाल तो 0.4 प्रतिशत शुल्क से शुरुआत होने के बाद भविष्य में शुल्क बढ़ने अथवा अन्य श्रेणियों के भुगतानों पर भी शुल्क लगाए जाने की आशंका व्यापारियों के बीच चिंता का विषय बना हुआ है। टैक्स को लेकर छोटे व्यापारियों के संबंध में केवल ट्रांजेक्शन की राशि को आधार बनाकर शुल्क व्यवस्था तय करना उचित नहीं है। यदि कोई छोटा व्यापारी एक लाख रुपये से अधिक का ट्रांजेक्शन करता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह एक लाख रुपये का मुनाफा कमा रहा है। केंद्र सरकार को केवल वढक शुल्क लगाने के फैसले की समीक्षा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि इस शुल्क से वास्तविक आर्थिक लाभ किसे हो रहा है। हमारे देश में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में काम करने वाली कई प्रमुख कंपनियों के विदेशी संबंध हैं। गूगल पे और अमेजॉन पे अमेरिकी कंपनियों से संबंधित है तो वहीं फोन पे भारतीय मूल की कंपनी है, लेकिन इसमें भी अमेरिकी निवेशकों का बड़ा निवेश और स्वामित्व से जुड़ा हुआ संबंध है। यूपीआई ट्रांजेक्शन में नई व्यवस्था करने के बाद अब सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि व्यापारियों से प्राप्त शुल्क का वितरण किन बैंकों, पेमेंट ऐप्स और सेवा प्रदाताओं के बीच होगा तथा इसमें विदेशी कंपनियों की क्या भूमिका होगी। डिजिटल भुगतान व्यवस्था का उद्देश्य व्यापार को सरल और सुविधाजनक बनाना होना चाहिए था, न कि छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना। टेक्स्ट ताई करने के बाद अब यह तो निश्चित है कि व्यापारी बड़ी पेमेंट लेने से बचेगें और मार्केट में एक बार फिर कैश का फ्लो देखने को मिलेगा। यहां व्यापारी और ग्राहक के बीच वाद विवाद और ना समझी का दौर शुरू होगा। व्यापारियों द्वारा ग्राहकों से अपील भी की जाने लगी है कि वह व्यापारियों की समस्या को समझते हुए नागम में लेनदेन करने की कोशिश करें। यह अपील व्यापारियों पर अतिरिक्त् शुल्क के आर्थिक बोझ को लेकर उनकी चिंता के संदर्भ में की जा रही है। ग्राहकों और व्यापारियों के बीच सहयोग से ही स्थानीय बाजारों को मजबूत बनाया जा सकता है, हालांकि स्थिति जितनी आसान नज़र आ रही है, उतनी बन पाएगी उसकी उम्मीदें कम ही है।



सुरेश हिंदुस्तानी

तकनीक ने मनुष्य को संवाद के ऐसे साधन उपलब्ध करा दिए हैं, जिनकी कल्पना कुछ दशक पहले तक असंभव लगती थी। अब एक क्लिक पर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से संपर्क स्थापित हो जाता है। हजारों मित्र, सैकड़ों समूह, लगातार आती सूचनाएं और हर क्षण सक्रिय रहने वाली आभासी दुनिया ने यह भ्रम पैदा कर दिया है कि मनुष्य पहले से कहीं अधिक जुड़ा हुआ है।



मनोज कुमार अग्रवाल

दुनिया की अदालतों में लंबित मुकदमों की कुल तादाद से अधिक तादाद हमारे इकलौते देश भारत में लंबित मुकदमों की है। हालत यह है कि लाखों लोगों को अपने जीवन में अदालत में लंबित मुकदमे का फैसला नहीं मिल पाता है हालांकि देश में कानून का संविधान का शासन है लेकिन यह कैसी कानून व्यवस्था है जिसमें न्याय पाने की लालसा में जिन्दगी बीत जाती है लेकिन न्याय नहीं मिलता है।और ऐसी लेटलतीकी भरी कानून व्यवस्था में कैसे किसीका विश्वास बना रह सकता है ? देश में बढ़ती अराजकता भ्रष्टाचार और अपराधों की अदालती न्याय व्यवस्था जिम्मेदार है क्योंकि अपराधी को पता है कि अदालत की सुनवाई में दशकों बीत जाते हैं और तब तक गवाह को डरा धमका कर या प्रलोभन देकर पक्षद्विही कर लिया जाएगा और अपराधी बाईज्जत बरी होने में सफल हो जाता है। यही वजह है कि देश में दोषसिद्धी (कनविकशन) की दर बहुत कम सिर्फ 54 फीसद है. कहा जाता है कि देर से मिलने वाला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है. लेकिन देश की अदालती प्रक्रिया इस तरह जटिल और दुरुह है कि लोग अदालतों के चक्कर लगाते जीवन के बहुमूल्य समय को बर्बाद कर देते हैं और जब अदालत से न्याय मिलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। भारत की अदालतों में इस समय लगभग 5.86 करोड़ से अधिक मामले लंबित (पेंडिंग) हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश भर में लगभग 5.86 करोड़ मामले अट-के हुए हैं। जिला व निचली अदालतों में सबसे अधिक करीब 5.2 करोड़ मामले निचली अदालतों में लंबित हैं। उच्च न्यायालयों में लगभग 64.97 लाख मामले लंबित हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में लगभग 95,000 मामले लंबित हैं। मुकदमों के लंबित होने के

सोशल मीडिया की भीड़ में अकेला होता व्यक्ति

लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक गंभीर सामाजिक विडंबना भी आकार ले रही है, संपर्क बढ़ रहे हैं, संवाद घट रहा है और भीड़ बढ़ने के बावजूद मनुष्य भीतर से अकेला होता जा रहा है। उसे आत्मीयता भरे शब्दों की प्रतीक्षा रहती है। लेकिन दुनिया के व्यक्ति केवल ज्ञान देने तक ही सीमित रहते हैं, साथ चलने को कोई तैयार नहीं होता। सोशल मीडिया ने दूरी अवश्य कम की है, लेकिन निकटता की परिभाषा बदल दी है। पहले किसी अपने से मिलने के लिए समय निकालना पड़ता था। आपने-सामने बैठकर बातचीत होती थी, चेहरे के भाव पढ़े जाते थे और मौन भी संवाद का हिस्सा होता था। अब किसी के जीवन में हमारी उपस्थिति कई बार केवल एक हल्लाईकल्लू, एक इमोजी या कुछ शब्दों की टिप्पणी तक सीमित हो गई है। जन्मदिन पर दर्जनों शुभकामनाएं मिल जाती हैं, लेकिन संकट की घड़ी में कंधा देने वाला व्यक्ति तलाशना कठिन हो रहा है। इसी कारण आज हर कोई अकेलेपन की गहराई में लगातार घुसता ही जा रहा है। यह बात सच है कि जो व्यक्ति से मिल

सकता है, उसे तकनीक कभी नहीं दे सकती। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव परिवार और समाज की संरचना पर भी दिखाई दे रहा है। एक ही घर में रहने वाले लोग कई बार अपने-अपने मोबाइल की स्क्रीन में व्यस्त रहते हैं। भोजन की मेज पर बातचीत के बजाय सूचनाओं की जांच होती है। बच्चे माता-पिता के साथ समय बिताने के बजाय डिजिटल मनोरंजन में डूबे रहते हैं और माता-पिता भी अपनी आभासी दुनिया में व्यस्त रहते हैं। परिणाम यह है कि घर भौतिक रूप से साथ होते हुए भी भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं। इसी से परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ती जाती हैं, और यही परिवार टूटने का एक बड़ा कारण भी है। इससे भी व्यक्ति अवसाद की ओर अग्रसर होता जाता है। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसने मनुष्य को स्वयं को प्रस्तुत करने का अभूतपूर्व मंच दिया, लेकिन स्वयं को समझने का अवसर कम कर दिया। यहां हर व्यक्ति अपने जीवन का चुना हुआ हिस्सा प्रदर्शित करता है। दूसरों के

जीवन की दिखाई देने वाली चमक जब लगातार हमारी आंखों के सामने रहती है, तो अनजाने में तुलना शुरू हो जाती है। हमें लगता है कि दूसरे हमसे अधिक सफल, अधिक खुश और अधिक संतुष्ट हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला जीवन अक्सर संपूर्ण जीवन नहीं, उसका चयनित अंश होता है। जीवन वही सार्थक है, जिसमें समाज और परिवार का साथ हो। किसी भी प्रकार की तुलना करना हानिकारक ही है। यही तुलना धीरे-धीरे आत्मसंतोष को प्रभावित करती है। व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविक उपलब्धियों के बजाय दूसरों की आभासी उपलब्धियों से स्वयं को मापने लगता है। लाइक और कमेंट सामाजिक स्वीकृति के नए पैमाने बन जाते हैं। पोस्ट पर प्रतिक्रिया कम मिले तो वैचैनी और अधिक मिले तो क्षणिक संतोष प्राप्त होता है। यह चक्र व्यक्ति को बाहरी मान्यता पर निर्भर करता जाता है। विडंबना यह है कि हजारों लोगों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी अपने मन की बात कहने के लिए एक विश्वसनीय व्यक्ति की तलाश कर सकता है।

कछुआ की गति से भी धीमी है देश की अदालतों की चाल

मुख्य कारण न्यायाधीशों की कमी होना भी है। देश में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 21 जज हैं, जबकि विधि आयोग ने 50 जजों की सिफारिश की थी। सरकार खुद बड़ी वादी है कुल लंबित मामलों में से लगभग 50% मामलों में सरकार खुद एक पक्ष या वादी है। भूमि और संपत्ति विवाद: लगभग 20% मामले लभिम और संपत्ति के विवादों से जुड़े हैं।प्रक्रियागत देरी भी एक बड़ी समस्या है। बार-बार तारीखें लेना, कागजी कार्रवाई में देरी और पुराने तौर-तरीके में कोई बदलाव नहीं आया है। आज देश में पीड़ितों को न्याय के इंतजार में वर्षों लग रहे हैं और अदालतों में जारी तारीख पर तारीख के गलत रवैये के चलते मुकद्दमों के लटकते चले जाने के कारण न्याय की प्रतीक्षा में ही लोगों की पूरी जिंदगी बीत रही है ऐसी ही चंद घटनाओं से आपको रूबरू कराते हैं 4 फरवरी को गुजरात हाई कोर्ट ने नवम्बर, 1996 से लटकते आ रहे 30 वर्ष पुराने एक मामले में पुलिस कांस्टेबल बाबूभाई प्रजापति को एक ट्रक ड्राइवर से 20 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में बाइज्जत बरी कर दिया। 2004 में निचली अदालत ने उसे 4 वर्ष की सजा सुनाई थी जिसके कारण बाबूभाई प्रजापति की नौकरी और पेंशन सब चली गई। बाबूभाई प्रजापति ने उक्त फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी। बरी होने के बाद बाबूभाई प्रजापति ने अपने वकील से कहा था, भरे जीवन से यह कलंक मिट गया, अब यदि भगवान मुझे उठा भी ले तो कोई दुख नहीं। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि फैसला आने के अगले ही दिन 5 फरवरी, 2026 को दिल् का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। 5 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानों में भारी कमियों के दृष्टिगत संदेह का लाभ देते हुए 2 इंजीनियरों वी. के. दत्ता और दिनेश गर्ग को 35 वर्ष पूर्व 20 सितम्बर, 1991 को उन पर लगे 1,800 रुपए रिश्वत मांगने के आरोपों से यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग को साबित करने में नाकाम रहा है। निचली अदालत ने वर्ष 2002 में इन्हें 2 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। 1 जुलाई को लखनऊ की सी.बी.आई. अदालत ने लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह की 8 अगस्त, 2002 को हत्या के लगभग 23 वर्ष बाद फैसला सुनाते हुए विक्रम यादव उर्फ कालिया,

पन्ना सिंह और बृजेश यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान अन्य आरोपी मन्नालाल, वेद प्रकाश व छोटेलाल मर चुके हैं। 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1996 के 30 वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए गुजरात सरकार के 2 कर्मचारियों (1 क्लर्क और 1 चपरासी) को बरी कर दिया क्योंकि उन पर अभियोग पक्ष अपना आरोप सिद्ध न कर सका। इन दोनों पर एक छात्र को वजीफे के लिए आय प्रमाण पत्र जारी करने के बदले में 20 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था और निचली अदालत ने उन्हें एक वर्ष की सजा सुनी थी। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने डबल मर्डर से जुड़े लगभग 45 वर्ष पुराने मामले में देश की न्यायिक प्रणाली की विफलता पर बहद सख्त और चिंताजनक टिप्पणी की। निचली अदालत को इस मामले का ट्रान्सल (सुनवाई)पूरा करने में ही 22 वर्ष लग गए। इसके बाद, जब मामले की अपील की गई, तो झारखंड हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाने में 22 वर्ष का लंबा समय लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस भयंकर देरी को न्यायिक व्यवस्था की विफलता करार देते हुए 70 वर्षीय आरोपी की सजा को सस्पेंड (स्थगित) करते हुए उसे रिहा कर दिया। अदालत ने गौर किया कि 6 आरोपियों में से 2 की मौत आरोप तय होने से पहले ही हो गई थी जबकि दोषी ठहराए गए 4 में से 3 आरोपियों की मौत हाई कोर्ट में ममला लम्बित रहने के दौरान हो गई थी। 1 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन बैंक के एक पूर्व ब्रांच मैनेजर को वर्ष 1991 से उसके विरुद्ध चल रहे 35 वर्ष पुराने भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उसके लगाए हुए आरोप पूर्णतः मनगढ़ंत हुए गए। अदालतों पर मुकद्दमों का भारी बोझ होने के चलते न्याय मिलने में विलंब को देखते हुए ही लोगों ने कई मामलों में स्वयं कानून हाथ में लेना शुरू कर दिया है और इसीलिए समय-समय पर लोगों द्वारा अपराध के शक में लोगों को पकड़ कर बिना सचवाई जाने ही पीट-पीट कर मार डालने के समाचार तक आने लगे हैं।इस तरह की नौबत न आए इसके लिए जहां देश की छोटी-बड़ी सभी अदालतों में जजों की कमी यथाशीघ्र दूर करने की आवश्यकता है, वहीं अदालतों में न्याय प्रक्रिया को चुस्त तथा और तेज करने की भी

जरूरत है। यदि अदालतों में पर्याप्त संख्या में जज ही नहीं होंगे तो फिर भला लोगों को समय पर न्याय किस प्रकार मिल सकता है। बिना किसी संदेह के, भारतीय अदालतों में मामलों की भारी तादाद में लंबित मामले न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आंकड़ों के अनुसार, देश की अदालतों में लंबित मामलों की कुल संख्या 5.4 करोड़ (54 मिलियन) से अधिक हो चुकी है, जिसमें पिछले एक दशक में लगभग 80% की भारी वृद्धि देखी गई है।इन लंबित मामलों का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 85% से अधिक) निचली या अधीनस्थ अदालतों में है, वहीं, सर्वोच्च न्यायालय में भी लगभग 85,000 मामले लंबित हैं। । स्वीकृत पदों का खाली होनाअधीनस्थ में न्यायाधीशों की संकीकृत पदों में से एक बड़ी संख्या खाली पड़ी रहती है। निचली अदालतों में हजारों पद और उच्च न्यायालयों में सैकड़ों पद लंबे समय से रिक्त हैं क्योंकि भर्ती और नियुक्ति की प्रक्रिया काफी धीमी और जटिल है। बुनियादी ढांचे या निचली अदालतों में कोर्ट हॉल, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (जैसे वीडियो कॉन्फ़रेंसिंग सुविधाएं) और सहायक कर्मचारियों (जैसे आशुलिपिक और क्लर्क) की भारी कमी है, जिससे दैनिक सुनवाई की गति धीमी हो जाती है। अंतर-विभागीय विवादों और अनावश्यक अपीलों के कारण अदालतों पर बोझ लगातार बढ़ता जाता है। प्रक्रियात्मक कमियां और स्थान अदालती प्रक्रियाओं में बार-बार मिलने वाली तारीखें , बार-बार की जाने वाली अपीलें, और मुकद्दमों के प्रबंधन की कुशल प्रणाली न होना मामले को सालों-साल खींचता है। वैकल्पिक विवाद समाधान का कम उपयोगमध्यस्था सुलह और लोक अदालतों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों का देश में अभी भी उतना प्रभावी और व्यापक उपयोग नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए ताकि छोटे मामलों को कोर्ट से बाहर ही सुलझा जा सके। सुधार के प्रयास:इस संकट से निपटने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुराने मामलों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष बेंचों का गठन करने जैसे कदम उठाए गए हैं। साथ ही, सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना का प्रस्ताव भी विचारधीन है। (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं।इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

यूपीआई शुल्क: सुविधाओं का विस्तार या उपभोक्ता पर बोझ?



ललित गर्ग

फिर भी इस बदलाव को केवल ह्यशुल्क लगा या नहीं लगाहू के प्रश्न तक सीमित करना उचित नहीं होगा। असली सवाल यह है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लंबे समय तक टिकाऊ कैसे बनाया जाए और उसकी लागत किसके हिस्से में जाए। यूपीआई की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी सरलता और लगभग बिना लागत की अनुभूति रही है।



दिखाई देती है। अनेक डिजिटल और उपभोक्ता सेवाएं पहले मुफ्त, अत्यंत सस्ती या भारी छूट के साथ उपलब्ध कराई जाती हैं। उपभोक्ता को उस सुविधा का अर्थस्र बनाया जाता है, बाजार में उसका व्यवहार बदलता है और प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने के बाद लागत की नई संरचना सामने आती है। ओला-उबर जैसी सेवाओं से लेकर ऑनलाइन व्यापार, डिजिटल सदस्यता और विभिन्न प्लेटफॉर्म सेवाओं तक इस मॉडल के अलग-अलग रूप दिखाई देते हैं। यह कहना उचित नहीं होगा कि हर मामले में यही रणनीति अपनाई जाती है, लेकिन उपभोक्ता के दृष्टिकोण से प्रश्न महत्वपूर्ण है-यदि किसी सेवा की दीर्घकालिक लागत है तो उसकी जानकारी शुरुआत से स्पष्ट क्यों न हो? यूपीआई के मामले में यह प्रश्न और गंभीर है क्योंकि इसके उपयोगकर्ता केवल शहरी मध्यमवर्ग नहीं हैं। छोटे दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू उद्यमी, ग्रामीण उपभोक्ता और पहली बार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े लोग भी इसके बड़े हिस्से हैं। सरकार की 2025 की प्रोत्साहन योजना में भी छोटे व्यापारियों के ₹.2,000 तक के भीम-यूपीआई भुगतान को शून्य एमडीआर के दायरे में रखते हुए ₹.1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ाना और भुगतान ढांचे को मजबूत करना था। इसलिए शुल्क की किसी भी व्यवस्था का पहला सिद्धांत होना चाहिए-छोटे भुगतान और छोटे कारोबार की रक्षा। ₹.100, ₹.500 या ₹.1,000 के भुगतान पर लागत बढ़ाने वाला मॉडल डिजिटल समावेशन की भावना के विपरीत जा सकता है। इसके विपरीत बड़े व्यावसायिक भुगतान से जुड़ी लागत को अलग तरीके से देखा जा सकता है, बशर्ते शुल्क

पारदर्शी, सीमित और पूर्व घोषित हो तथा उसका भार अनुचित रूप से ग्राहक पर न डाला जाए। यहां डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। यूपीआई के व्यापक प्रसार ने कार्ड भुगतान की रोजमर्रा के छोटे भुगतानों में पीछे धकेला है। यदि यूपीआई के कुछ बड़े व्यापारी लेन-देन पर लागत बढ़ती है तो कुछ कारोबारी वैकल्पिक भुगतान माध्यमों की ओर देख सकते हैं। कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या अन्य डिजिटल माध्यम फिर कुछ क्षेत्रों में अधिक सक्रिय हो सकते हैं। इससे भुगतान बाजार में विविधता बढ़ सकती है, लेकिन यदि उपभोक्ता को हर माध्यम में अलग-अलग शुल्क, सुविधा और शर्तों का सामना करना पड़े तो डिजिटल भुगतान की सरलता कमजोर भी हो सकती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य केवल माध्यम बदलना नहीं, बल्कि उपभोक्ता को बेहतर विकल्प देना होना चाहिए। दूसरी ओर यूपीआई को मुफ्त बनाए रखने की भी कीमत है। भुगतान प्रणाली को चौबीसों घंटे चलाने के लिए बैंकिंग सर्वर, डेटा सेंटर, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने वाली प्रणालियां, ग्राहक सहायता और तकनीकी उन्नयन पर लगातार खर्च होता है। जैसे-जैसे लेन-देन बढ़ते हैं, वैसे-वैसे विश्वसनीयता और क्षमता पर निवेश की आवश्यकता भी बढ़ती है। सरकार की 2025 की योजना में भी तकनीकी विफलताओं को घटाने और सिस्टम अपटाइम सुधारने को प्रोत्साहन से जोड़ा गया था। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि यूपीआई की हर सेवा हमेशा मुफ्त रहे या नहीं, सवाल यह होना चाहिए कि उसकी लागत का न्यायपूर्ण और पारदर्शी वितरण कैसे हो। सरकार, बैंक, फिन्टेक कंपनियां और भुगतान नेटवर्क यदि इस व्यवस्था से आर्थिक लाभ लेते हैं तो उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा,

विश्वसनीयता और नवाचार पर पर्याप्त निवेश हो। शुल्क का उद्देश्य केवल राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि बेहतर डिजिटल भुगतान व्यवस्था के निर्माण से जुड़ा होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात उपभोक्ता विश्वास की है। डिजिटल अर्थव्यवस्था विश्वास पर चलती है। यदि आज किसी सेवा को 'मुफ्त' बताया जाए और कल अचानक उसकी लागत सामने आए, तो उपभोक्ता में अविश्वास पैदा हो सकता है। इसलिए भविष्य में किसी भी डिजिटल भुगतान व्यवस्था की शुरुआत करते समय उसकी संभावित लागत, शुल्क संरचना और उसे लागू करने की परिस्थितियां पहले से स्पष्ट होनी चाहिए। उपभोक्ता को यह पता होना चाहिए कि कौन-सी सेवा नि:शुल्क है, किस पर लागत है, लागत कौन वहन करेगा और उसका अधिकतम स्तर क्या होगा। भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार कर रहा है। ऐसे समय में यूपीआई की सफलता को केवल लेन-देन की संख्या से नहीं, बल्कि उसकी स्थिरता, सुरक्षा, पहुंच और उपभोक्ता विश्वास से मापना होगा। भारत की विकास-आकांक्षाओं के लिए उत्पादकता, नवाचार और मजबूत डिजिटल आधारभूत ढांचा महत्वपूर्ण हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी भारत की उत्पादकता और नवाचार क्षमता की दीर्घकालिक विकास से जोड़ता है। यूपीआई शुल्क की बहस इसलिए वास्तव में 'शुल्क बनाम मुफ्त' की बहस नहीं है। यह उस आर्थिक दर्शन की प्रतीक्षा है जिसमें डिजिटल सुविधा आम आदमी तक सस्ती, सरल और सुरक्षित रूप में पहुंचती है। छोटे भुगतान मुफ्त रहें, छोटे व्यापारियों पर अनावश्यक भार न पड़े, बड़े व्यवसायिक लेन-देन में लागत की ताकिक व्यवस्था हो, शुल्क की जानकारी पहले से सार्वजनिक हो और उससे प्राप्त संसाधन भुगतान प्रणाली की सुरक्षा व क्षमता बढ़ाने में लगे, ऐसा संतुलन ही टिकाऊ रास्ता हो सकता है। भारत को डिजिटल भुगतान का विस्तार रोकना नहीं, बल्कि उसकी अगली पीढ़ी तैयार करनी है। यूपीआई की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने भुगतान को बैंक की शाखा और बटुए की सीमा से निकालकर मोबाइल की स्क्रीन तक पहुंचा दिया। अब अगली चुनौती यह है कि यह सुविधा आर्थिक रूप से टिकाऊ भी रहे और आम उपभोक्ता के लिए सहज भी। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखने वाले भारत में डिजिटल भुगतान केवल तकनीकी नहीं, आर्थिक जीवन की धड़कन है। इसलिए इसकी कीमत तय करते समय बाजार की कमाई से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए-'उपभोक्ता का विश्वास, छोटे कारोबार की क्षमता और डिजिटल भारत की दीर्घकालिक विश्वसनीयता'। (लेखक, पत्रकार, स्तंभकार) (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं।इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

देवभूमि उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड शासन



देवभूमि उत्तराखण्ड



शान्ति, रोमांच व आस्था का गंतव्य

“ 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखण्ड, इन दोनों ही स्तंभों को लगातार मजबूत कर रहा है। ये दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा। ”

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

“ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखण्ड निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। तीर्थाटन एवं पर्यटन की दृष्टि से लोग यहां आये, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं ताकि पर्यटक शीतकाल में पर्यटन के साथ तीर्थों का भी आनन्द ले सकें। ”

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

होम स्टे से ग्रामीण पर्यटन को लग रहे पंख

शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर, पहाड़ों की सुंदर वादियों में किसी छोटे से गांव में आतिथ्य सत्कार लेते पर्यटक उत्तराखण्ड के होम स्टे को सराहते हैं। होम स्टे अब उत्तराखण्ड में ग्रामीण पर्यटन को नई पहचान दे रहा है।

पलायन प्रभावित गांवों में आजीविका के साधन विकसित करने के लिए शुरु की गई, दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) योजना अपने आप में सफलता की कहानी बयां करती है।

योजना का मकसद देशी विदेशी पर्यटकों को उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षित करते हुए, उन्हें उत्तराखण्ड की समृद्ध संस्कृति, खान पान से परिचित कराने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी को मजबूत करना है। योजना के तहत राज्य में अब तक 5703 से अधिक होम स्टे

पंजीकृत हो चुके हैं।

इसके साथ ही सरकार ट्रेकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना के तहत चिह्नित ट्रेकिंग ट्रैक्शन सेंटर से दो किमी के दायरे में आने वाले

योजना के तहत राज्य में अब तक 5703 से अधिक होम स्टे पंजीकृत

गांवों में होम स्टे निर्माण के लिए अनुदान दे रही है। योजना के तहत अब तक 06 जनपदों के 101 गांवों को अधिसूचित करते हुए, पांच सौ से अधिक लोगों को चिह्नित किया जा चुका है। इसके साथ ही सरकार वीरचंद्र सिंह गढ़वाली



पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत वाहन मद और पर्यटन इकाई निर्माण के लिए अनुदान प्रदान कर रही है। जिसमें अब तक 7300 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड पर्यटन प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व का अमृत मिश्रण है। यहां हिमालय की गोद में बसे प्रसिद्ध स्थल सैलानियों को आकर्षित करते हैं। ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग और वन्यजीव अभ्यारण्य भी रोमांच प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं।

प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच का अद्भुत समागम देवभूमि उत्तराखण्ड

इको-टूरिज्म हो या वाइल्डलाइफ टूरिज्म या रोमांचकारी अनदेखी बर्फीली चोटियां और रोमांचकारी स्कीइंग और माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रेकिंग के रोमांचकारी रास्ते, आपको यहां वह सब कुछ मिल सकता है जिसके लिए कई देशों की यात्रा करनी पड़ सकती है। उत्तराखण्ड अब हरित पर्यटन, माइंडफुल ट्रेवल,

वन्यजीव यात्रा, प्राकृतिक पर्यटन के लिए जाना जाता है। बेहतर पर्यटन नीतियों और उच्च संभावनाओं को देखते हुए विगत वर्षों में राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर निवेश तो हुआ ही है साथ ही भविष्य में कई बड़े निवेशकों ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाशी हैं। साहसिक गतिविधियों हेतु उत्तराखण्ड अमरता हुआ पर्यटन स्थल बनता जा रहा है।

- उत्तराखण्ड के जखोल, सूपी, हर्षिल और गुंजी गांवों को भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में पुरस्कृत किया गया।
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत सीमांत के 51 गांवों का चयन कर किया जा रहा सुनियोजित विकास।
- कुशल प्रबंधन से चारधाम यात्रा पर रिकॉर्ड संख्या में आए श्रद्धालु।
- राज्य में पहली बार शीतकालीन यात्रा का हुआ शुभारंभ।
- मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के अन्तर्गत 48 मंदिरों तथा अन्य धार्मिक स्थलों को सर्किट के रूप में जोड़ने का कार्य गतिमान।
- महासू मन्दिर, हनोल के मास्टर प्लान को दी गई मंजूरी।

आर्थिक समावेशन, पर्यावरणीय स्थिरता और निवेशक अनुकूलता सुनिश्चित करती उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2023

उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2023 का उद्देश्य राज्य को एक प्रमुख सतत् और निवेश-अनुकूल पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।



उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2023 राज्य को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त पर्यटन केन्द्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक व्यापक और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह नीति

31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी और पर्यटन आधारित विकास को गति देने के साथ आर्थिक समावेशन, पर्यावरणीय स्थिरता और निवेशक अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई।

संस्थागत ढांचा और नीति की प्राथमिकताएं

यह नीति पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) को सक्षम बनाने और हॉस्पिटैलिटी, वेलेनेस, एडवेंचर, हेरिटेज और ग्रामीण पर्यटन जैसे विविध क्षेत्रों में निवेश लाने पर केन्द्रित है।

नीति के क्रियान्वयन के लिए उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड (यूटीडीबी) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसमें 50 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए राज्य स्तरीय सशक्त समिति (एसएलईसी) का गठन किया गया है। साथ ही, 50 करोड़ रुपये तक की एमएसएमई परियोजनाओं के लिए जनपद स्तरीय सशक्त

समितियां (डीएलईसी) बनाई गई हैं। वहीं, परियोजनाओं की भौतिक जांच और सत्यापन के लिए जनपद स्तरीय पर्यटन समितियां (डीएलसीटी) गठित की गई हैं।

योग्य परियोजनाएं और निवेश प्रोत्साहन

इस नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पर्यटन इकाइयों को योग्य माना गया है। इसमें होटल, रिसॉर्ट, विरासत भवन, रोपवे, ईको-लॉज, योग एवं वेलेनेस सेंटर, मनोरंजन पार्क, साहसिक पर्यटन सुविधाएं आदि शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम निवेश और बुनियादी ढांचे की शर्तें तय की गई हैं, जिससे गुणवत्ता और निवेश को बढ़ावा मिले।

पौराणिक मंदिरों के लिए संजीवनी का काम कर रही...मानसखंड मंदिर माला योजना

मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत प्रदेश सरकार कुमाऊं क्षेत्र के 48 पौराणिक मंदिरों के आस पास अवस्थापना संबंधित विकास कार्य कर रही है। प्रथम चरण में इसके लिए 16 मंदिरों का चयन किया गया है। इसमें जागेश्वर मंदिर, गोलू देवता मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, कसारदेवी, नंदादेवी, पाताल भुवनेश्वरी गुफा, हाट कालिका, पूर्णागिरी, नयना देवी, बालेश्वर, कैची धाम, वाराही देवी, बैजनाथ, बागनाथ, चैती बाला सुंदरी मंदिर शामिल हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा में झांकर सैम, नैथना देवी, विंध्यावासिनी, मल्लिका देवी, स्याही देवी मंदिर, पिथौरागढ़ में मोस्टमान्, बेरीनाग, मलयनाथ, थलकेदार, कोटगिरी मंदिर शामिल हैं।



साथ ही उधमसिंहनगर में अटारिया मंदिर, नानकमता, मोटेश्वर महादेव, वनखंडी महादेव, चम्पावत में मीठा रीठा साहिब, गुरु गोरखनाथ मंदिर, मानेश्वर मंदिर, बालेश्वर, देवीधार, बागेश्वर जिले में कोट भ्रामरी, शिखर भनार और नैनीताल जिले में स्थित गोलू देवता, गिरिजा देवी मंदिर, हनुमान मंदिर, सोमवारी महादेव, देवगुरु बहुस्पतिधाम, हनुमान गढ़ी मंदिर मानसखंड मंदिर माला में शामिल किए गए हैं।

इससे कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों के आस पास आर्थिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है।

एशियाड: भारतीय खिलाड़ियों के लिए बुक कराने पड़े अतिरिक्त कमरे

शटलर-वेटलिफ्टर भी एयरपोर्ट पर करते रहे इंतजार

नई दिल्ली। एशियाई खेलों के शुरू होने से पहले ही जापान में भारतीय खिलाड़ियों की परेशानियां दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। आयोजकों की खामी के चलते रोइंग, शूटिंग के बाद बैडमिंटन और वेटलिफ्टिंग टीम को नागोया में कई घंटे एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। नागोया में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की ओर से बुक कराए गए कमरों की संख्या पहले से ही कम कर दी गई है। 20 और 21 सितंबर को सभी भारतीय खिलाड़ी नागोया पहुंच रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए कमरों की देखते हुए भारतीय दल के शेफ डी मिशन सहदेव यादव ने एजेंट के जरिये बृहस्पतिवार को होटल में 15 अतिरिक्त कमरे बुक कराए हैं। आयोजकों ने भारतीय खिलाड़ियों के तकरीबन 40 कमरे कम बुक किए हैं।



खिलाड़ियों के लिए बुक नहीं थे कमरे

सहदेव यादव का कहना है कि अभी खिलाड़ियों के ठहरने को लेकर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन 20 और 21 सितंबर को जब पूरा भारतीय दल यहां पहुंचेगा तो सभी के रुकने के लिए कमरे नहीं हैं। कोई परेशानी न हो इसलिए नागोया से एक घंटे की दूरी पर 15 अतिरिक्त कमरे बुक कराए गए हैं। जिन खिलाड़ियों को यहां ठहरने की व्यवस्था नहीं होगी। उन्हें इस होटल में ठहराया जाएगा।

मीरा भी एयरपोर्ट पर फंसी रहीं

भारतीय खिलाड़ियों को ट्रांसपोर्ट के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ा रहा है। भारतीय शूटिंग टीम को ट्रांसपोर्ट नहीं मिलने से उनकी ट्रेनिंग बाधित हुई है। बैडमिंटन टीम बुधवार की रात तकरीबन छह घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसी रही। यही नहीं कोच विजय शर्मा के साथ बृहस्पतिवार को नागोया पहुंची मीराबाई चानू को भी एयरपोर्ट पर कई घंटे बैठे रहना पड़ा। बुधवार को रोइंग टीम को कूज शिप में ठहरने के लिए नौ से 10 घंटे इंतजार करना पड़ा था। रोइंग टीम ने अपने पास से खाना खाया। हालांकि आईओए ने रोइंग दल से कहा है कि उनके खाने के पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा।

चार खिलाड़ियों को बदला जाएगा

आईओए ने चार चोटिल खिलाड़ियों के बदलाव के लिए आयोजकों से प्रार्थना की है। चोटिल लॉगन जंपर शाहनवाज खान की जगह डेविड सोलोमोन, क्रिकेटर वरुण चक्रवर्ती की जगह विजय निगम, तलवारबाज प्राची मोहन की जगह अनुग्रिया और रग्बी खिलाड़ी प्रभाती हंसदा की जगह मामा नायक को बदलने के लिए कहा गया है। इन बदलाव के लिए आयोजकों की हरी झंडी का इंतजार है।

शेफाली-श्री चरणी का धमाका!

भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में

निशिन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। जापान के निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने जापान को आठ विकेट से हरा दिया। 58 रन के लक्ष्य को भारत ने पांच ओवर में हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने विनिंग सिक्स लगाया। वह 15 गेंद में छह चौके और दो छक्कों की मदद से 40 रन बनाकर नाबाद रहीं। वहीं, ऋचा घोष छह गेंद में दो चौके की मदद से 12 रन बनाकर नाबाद रहीं। अब सेमीफाइनल में 20 सितंबर को भारत का सामना बांग्लादेश से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में उसी दिन पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों आमने-सामने होंगी।

जापान की पारी

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस

जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। जापान की टीम 19.5 ओवर में 57 रन पर सिमट गई थी। टीम को पहला झटका सातवें ओवर में लगा था। हालांकि, इसके बाद जैसे ही पहला विकेट गिरा, जापान की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हारुना इवासाकी 10 रन, अयाका कातो स्टेफर्ड 47 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हुईं। ये दोनों ओपनर्स ने ही टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। इसके बाद कप्तान माई यानागिदा खाता खोले बिना पवेलियन लौटीं।

वहीं, एरिका ओडा पांच रन, शिमाको कातो तीन रन, अकारी निशिमुरा कानो दो रन, हीनासी गोतो एक रन बना सकीं। अहिल्या चंदेल और एरिका तोगुची कि्वन खाता खोले बिना आउट हुईं। भारत के लिए श्री चरणी ने चार विकेट झटकें, वहीं शेफाली वर्मा को दो विकेट मिले। श्रेयांका पाटिल और दीप्ति शर्मा को एक-एक विकेट मिला।

पाकिस्तान की टीम को जूझना पड़ा

वहीं, पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में थाइलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। पाकिस्तान को थाइलैंड पर जीत बहुत मुश्किल से मिली थी। पाकिस्तान ने थाइलैंड के दिए 92 रन के लक्ष्य को हासिल करने में अपने सात विकेट गंवा दिए थे। निर्धारित 11 ओवर के मैच में पाकिस्तान को दो गेंद पहले जीत मिली थी।

बांग्लादेश भी अंतिम-चार में

इसके अलावा बांग्लादेश ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उसका और चीन का सेमीफाइनल मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। बेहतर सीडिंग की वजह से बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में उसका सामना 20 सितंबर को भारत और जापान के बीच जीत दर्ज करने वाली टीम से होगा।

शिद्दत से काम करो और दिल से चाहो तो कैसे नहीं होगा: मनीषा



नई दिल्ली । भारतीय रेसलर मनीषा एशियन गेम्स 2026 में अपना डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। उनके सामने एक नई चुनौती है क्योंकि उन्होंने 62 किलोग्राम कैटेगरी से 57 किलोग्राम कैटेगरी में बदलाव किया है। इस बदलाव के दौरान उन्होंने अपनी ताकत और तकनीक को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है, साथ ही दोनों तरह के स्टायंस (मुद्रा) से रेसलिंग करने की काबिलियत विकसित करके अपने खेल में बड़ा बदलाव किया है। मनीषा ने कहा, 'मैं पहले ज्यादातर दाईं ओर से खेलती थी, लेकिन अब मैंने बाईं ओर से भी खेलना शुरू कर दिया है। मैं दोनों स्टायंस पर काम करने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि मैं दोनों तरफ से खेलने में सहज महसूस करना चाहती हूं। मैं अपनी ताकत और तकनीक पर काम कर रही हूं, लेकिन सबसे जरूरी बात अपनी सोच बदलना और नई कैटेगरी के हिसाब से खुद को ढालना भी है।'

एशियाई खेल: भारत के लिए सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं ये पांच खिलाड़ी

स्वताश में भी मिल सकती है सफलता



जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीती थी। वह यह मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थीं। अनाहत अपनी हालिया फॉर्म को अगर बरकरार रखने में सफल रहीं, तो वह देश की झोली में मेडल डाल सकती हैं।

अनुष्का यादव: एशियन गेम्स 2026 की एथलेटिक्स टीम में जगह बनाने वाली अनुष्का यादव टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से छाप छोड़ सकती हैं। अनुष्का हैमर थ्रो स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं। अब वह एशियाई खेलों में दमदार प्रदर्शन करके विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने को बेकरार होंगी।

आयुष शेट्टी: बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड



चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने अपने खेल से हर किसी को हैरान कर दिया था। उन्होंने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी को हराते हुए बड़ा उलटफेर किया था। 21 वर्षीय आयुष पहली बार एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने जा रहे हैं। 6 फीट और 4 इंच का यह खिलाड़ी अपनी दमदार स्मैश और खेल के बूते एशियन गेम्स में भारत को मेडल खिला सकते हैं।

सिंदूला दास: टेबल टेनिस में सिंदूला ने अपने खेल से हर किसी का ध्यान खींचा है। सिंदूला की उम्र महज 17 साल है, लेकिन अपनी फुर्ती और शानदार खेल से वह बड़ी सी बड़ी खिलाड़ियों पर हावी नजर आई हैं।

34 गेंदों में 108 रन

भारत-अफगानिस्तान... टूट गए टी20 के 12 रिकॉर्ड्स

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने ऐसी पारी खेली, जिसने टी20 क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में कई नए पन्ने जोड़ दिए। उन्होंने महज 34 गेंदों में 108 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 317.64 रहा। अभिषेक ने अपनी पारी में नौ चौके और 11 छक्के लगाए। उनकी इस पारी का सबसे बड़ा आकर्षण 30 गेंदों में पूरा हुआ शतक रहा। यह भारत की ओर से टी20 अंतरराष्ट्रीय में लगाया गया सबसे तेज शतक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था, जिन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाया था, लेकिन अभिषेक का रिकॉर्ड सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने किसी पूर्ण सदस्य देश के खिलाफ भी सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

30 गेंदों में शतक, भारत के लिए सबसे तेज

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक है। इससे पहले भारत के लिए सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था। रोहित ने 22 दिसंबर 2017 को इंदौर में श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाया था। अभिषेक ने इस रिकॉर्ड को पांच गेंद से बेहतर किया। इतना ही नहीं, किसी पूर्ण सदस्य देश के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में भी यह सबसे तेज शतक है। इससे पहले न्यूजीलैंड के फिन एलन ने 2026 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 33 गेंदों में शतक लगाकर यह रिकॉर्ड बनाया था।



कैमरन बैनक्रॉफ्ट को नौ महीने के लिए निलंबित किया गया था। उस दौर के लगभग आठ साल बाद, स्मिथ 9 अक्टूबर से डरबन में शुरू होने वाली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ दक्षिण अफ्रीका दौरे की तैयारी कर रहे हैं। स्मिथ ने कहा, 'निलंबन से जुड़ी घटनाओं को पूरी तरह भूलना मुश्किल है। दक्षिण अफ्रीका छोड़ने के बाद मीडिया में उन्हें जबरदस्त चर्चा मिली थी। '

102 रन सिर्फ चौके-छक्कों से

अभिषेक ने अपनी 108 रन की पारी में 102 रन सिर्फ चौकों और छक्कों से बनाए। यानी उनकी कुल पारी के 94.44 प्रतिशत रन बाउंड्रीज से आए। पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाने वाले बल्लेबाज की पारी में बाउंड्रीज से आए रनों का यह सबसे बड़ा अनुपात है। इससे पहले यह रिकॉर्ड मुहम्मद फहद के नाम था। उन्होंने 2025 में बुल्गारिया के खिलाफ 120 रन बनाए थे,

जिसमें 112 रन चौकों और छक्कों से आए थे। यह 93.33 प्रतिशत था। अभिषेक ने इस मामले में भी नया रिकॉर्ड बना दिया। उनकी 108 रन की पारी में सिर्फ छह रन ऐसे रहे, जो चौके या छक्के के अलावा आए।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय... तीसरा सबसे तेज शतक

अभिषेक का 30 गेंदों में आया शतक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में तीसरा सबसे तेज शतक है। उनसे आगे सिर्फ एस्टोनिया के साहिल चौहान और तुर्किये के मुहम्मद फहद हैं। साहिल चौहान ने 2024 में साइप्रस के खिलाफ 27 गेंदों में शतक लगाया था, जबकि मुहम्मद फहद ने 2025 में बुल्गारिया के खिलाफ 29 गेंदों में यह कारनामा किया था। अभिषेक शर्मा ने अपने शतक तक पहुंचने के लिए पारी के 8.3 ओवर का समय लिया। पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय में यह किसी बल्लेबाज के व्यक्तिगत शतक तक पहुंचने के लिए दूसरा सबसे कम ओवर है। इस मामले में भी उनसे आगे मुहम्मद फहद हैं। फहद ने 2025 में बुल्गारिया के खिलाफ सिर्फ 7.4 ओवर में अपना शतक पूरा कर लिया था। यानी अभिषेक ने यहां भी एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जहां उनसे आगे सिर्फ एक बल्लेबाज है। अभिषेक की पारी का असर सिर्फ उनके व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं रहा। भारत ने शुरूआती छह ओवरों में ही ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया, जो उसके टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में नया रिकॉर्ड बन गया। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ शुरूआती छह ओवरों में बिना कोई विकेट गंवाए 100 रन बनाए। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर 95 रन था, जो उसने 2025 में वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। उस दौरान भारत ने एक विकेट गंवाया था। दिलचस्प बात यह भी है कि उपलब्ध गेंद-दर-गेंद आंकड़ों के अनुसार भारत से पहले पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय में आठ टीमों पावरप्ले में 100 या उससे ज्यादा रन बना चुकी थीं। अब भारत भी इस सूची में शामिल हो गया। अभिषेक ने अफगानिस्तान के खिलाफ 108 रन की पारी के दौरान 11 छक्के लगाए।